www.cgfrontline.com

# छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

वर्ष: 01 | अंक: 68 | जशपुर, 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) | पृष्ठ: 08 | मूल्य: 01 रूपये

## पीडब्ल्यूडी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 91 सब इंजीनियर्स के तबादले

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। विभाग ने प्रशासनिक आधार पर 91 उप अभियंताओं (सिविल) के तबादला आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 26 अक्टूबर को मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

### रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक बदलाव

जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों की पदस्थापना रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, जशपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, राजनांदगांव सहित विभिन्न संभागों में बदली गई है। इसके साथ ही सेतु संभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यालयों में भी नई पदस्थापना की गई है। कुछ अधिकारियों को एक संभाग से दूसरे संभाग में भेजा गया है, जबकि कुछ को मुख्य अभियंता कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय और उपसंभाग स्तर पर नई जिम्मेदारी दी गई है।

### प्रमुख तबादले

दीप कुमार चक्राकर को रायपुर संभाग क्र.-3 से गरियाबंद संभाग भेजा गया, फारूक इशराक को नवा रायपुर से दुर्ग संभाग, चुन्नू लाल साहू को बलौदाबाजार से रायपुर संभाग क्र.-3, मंगल प्रसाद चक्राकर को महासमुंद से विधानसभा रायपुर संभाग, अंशुमान सिंह को गरियाबंद से धमतरी, संतोष कुमार साहू को गरियाबंद से विधानसभा रायपुर, आर.के. देशमुख को धमतरी से महासमुंद संभाग, सेतु संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और चांपा में भी अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर हैं और आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेंगे। उप अभियंताओं की भूमिका सड़क, भवन निर्माण कार्यों की तकनीकी निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण में महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में इस फेरबदल से विभागीय कामकाज के संचालन में नया वितरण होगा।

# प्रदेश प्रभारी का नया तेवर, सख्त पहरा और 'भैया वाली राजनीति' पर ब्रेक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**रायपुर।** प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ आते ही सत्ता-संगठन के समीकरण बदल गए हैं। सहज और सरल माने जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अब मजबूत सुरक्षा कवच मिल गया है, जिसका असर सरकार और प्रशासन पर दिख सकता है। स्मृति ईरानी के आक्रामक तेवर ने उन नेताओं की अकड़ ढीली कर दी है जो वरिष्ठता और धौंस के बल पर सियासत चला रहे थे। अब कुर्सी पर बने रहने और वजूद बचाए रखने के लिए परफॉर्मेंस ही एकमात्र पैमाना होगा।

### अब सिर्फ काम और परिणाम

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चली आ रही 'भैया वाली राजनीति' यानी मेल-मिलाप और बिना जवाबदेही की सियासत के दिन लद गए हैं। स्मृति ने रायपुर पहुंचते ही स्वागत की औपचारिकता को दरकिनार कर सीधे फील्ड रिपोर्ट पर बात की। केंद्रीय नेतृत्व का संदेश साफ है कि यदि संगठन और सरकार में रहना है तो नतीजे देने होंगे। जो नेता कागजी बैठकों और बयानों से काम चलाते थे, उन्हें अब बूथ स्तर तक पसीना बहाना पड़ रहा है।

### प्रेशर की राजनीति बंद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने मृदुभाषी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी यह सहजता कई बार प्रशासनिक फैसलों में भारी पड़ रही थी। साय मंत्रिमंडल में अधिकांश नए चेहरे होने से कुछ वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों और रसूखदार विधायकों का अप्रत्यक्ष दबाव बना हुआ था।

नीतिगत फैसलों में देरी पर उंगली सरकार पर उठती थी। ऐसे में स्मृति ईरानी को भेजना सीएम की सरकार को मजबूत सुरक्षा कवच देने जैसा है। उनके सख्त निर्णयों ने मुख्यमंत्री के लिए उन फैसलों को लेना आसान कर दिया है, जिनमें पहले असहजता महसूस होती थी।

### नए संगठन महामंत्री पर नजर

मंत्रिमंडल गठन के बाद से विभागों में वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप और मंत्रियों-संगठन के बीच तालमेल की कमी को लेकर सुगबुगाहट थी। अब नए प्रदेश महामंत्री (संगठन) कर्मवीर सिंह और प्रभारी स्मृति ईरानी की जोड़ी ने 'दबाव की सियासत' पर प्रहार किया है। अब सरकार में किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी नहीं, सामूहिक और अनुशासित निर्णय सर्वोपरि होंगे। बिलासपुर से रायपुर और सरगुजा से बस्तर तक संदेश साफ है सिफारिशों के दिन खत्म।

### मंत्रियों-विधायकों पर कड़ा पहरा

स्मृति द्वारा लाई गई जमीनी रिपोर्ट और मंत्रियों के कामकाज के पोस्टमार्टम ने हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली से पूरा होमवर्क करके आईं प्रभारी ने सुस्ती दिखाने वाले मंत्रियों की फेहरिस्त खोल दी है। दीपावली से पहले या राज्य स्थापना दिवस के आसपास संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की तलवार सुस्त मंत्रियों पर लटकी है।

### जमीनी कार्यकर्ताओं में लौटी ऊर्जा

इस कवायद का सकारात्मक पहलू मैदानी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। सत्ता आने के बाद खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे और वीआईपी कल्चर से त्रस्त कार्यकर्ता राहत की सांस ले रहे हैं। स्मृति के दौरे ने साबित किया है कि भाजपा हवा-हवाई दावों के बजाय कैडर-बेस्ड और रिजल्ट-ओरिएंटेड कार्यशैली की ओर लौट रही है। आगामी नगरीय चुनावों के लिए भाजपा अब पूरी तरह 'फाइट मोड' में है।

> मंत्रियों से नाराजगी के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, 'नो कमेंट्स।' वहीं, मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, 'जिसके ऊपर दायित्व होगा, थोड़ी शिकायत तो होगी ही।' बैठक के बाद कई मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए नजर आए। मंत्री लखनलाल देवांगन अन्य मंत्रियों के निकलने से करीब एक घंटे पहले ही कार्यालय से रवाना हो गए।

## खड़गे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, बीजेपी ने फूंका पुतला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**रायपुर।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द कांग्रेस की सोच दिखाते हैं।

भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने कहा कि बोलने का अधिकार सभी को है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं गिरानी चाहिए। मंत्री ओपी चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद संतोष पांडेय ने भी विरोध जताया है।

वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खड़गे ने भाषण में देश की समस्याएं भी उठाईं, लेकिन भाजपा उन पर बात करने के बजाय एक टिप्पणी को लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है।

### भाजयुमो ने फूंका पुतला

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दुर्ग, धमतरी, कोंडागांव समेत कई जिलों में खड़गे का पुतला फूंका और माफी मांगने की मांग की।क्या कहा था खड़गे ने? पटना में रविवार को बापू सभागार में कांग्रेस के कार्यक्रम में खड़गे मोदी सरकार पर बोल रहे थे। तभी एक कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी जी नहीं जाने वाले, जब तक विद्रोह नहीं होगा सरकार नहीं हटेगी। इस पर खड़गे ने गुस्से में कहा- 'मोदी क्या उसका बाप भी जाएगा'। यह बात उन्होंने 3 बार दोहराई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने टिप्पणी करने वाले शख्स की पिटाई कर दी।

### पटना में शिकायत दर्ज

पटना के कोतवाली थाने में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा कुमार सिंह ने खड़गे के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने पीएम के पिताजी पर अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दीं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस ने मोदी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों।

## एयरपोर्ट पर बड़ी विमान सेवा की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन, उल्टा चलकर जताया विरोध

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**बिलासपुर।** हवाई सेवा की सुविधाओं में कटौती के विरोध में अनोखा प्रदर्शन हुआ। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने सुविधाओं में कटौती के विरोध में उल्टा मार्च निकाला। धरना स्थल राघवेंद्र राव सभा भवन से कलेक्टोरेट तक यह रैली निकाली गई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति का यह आंदोलन बीते 7 साल से लगातार जारी है। आंदोलन के सात साल पूरे होने पर आयोजित इस उल्टी रैली में कई सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

### कई संगठनों का समर्थन

आंदोलन को जिला अधिवक्ता संघ, मर्चेंट एसोसिएशन, व्यापारिक संगठनों, जिला उद्योग संघ, आईएमए, होटल एसोसिएशन, क्रिकेट संघ, हॉकी संघ, रेलवे मेंस कांग्रेस सहित कई संगठनों का समर्थन मिला है।

समिति के सदस्य विजय पाण्डेय और विनय शुक्ला ने बताया कि बिलासपुर के बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट से मार्च 2021 में व्यावसायिक उड़ानें शुरू हुई थीं। हालांकि, रनवे की लंबाई लगभग 1500 मीटर होने के कारण केवल छोटे विमानों का ही संचालन हो पा रहा है। बोइंग जैसे बड़े विमान नहीं उतर पा रहे हैं। समिति की प्रमुख मांग है कि रनवे का विस्तार कर इसे 4सी श्रेणी का एयरपोर्ट विकसित किया जाए, ताकि बड़े विमानों का संचालन हो सके और महानगरों तक सीधी हवाई सेवा शुरू हो सके।

## नौकरी के नाम पर रूस में फंसा छत्तीसगढ़ का युवक, भारतीय दूतावास नहीं जाने दिया

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नौकरी की तलाश में रूस गया युवक 7 अक्टूबर से लापता है। परिवार का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। युवक की बहन ने आरोप लगाया है कि उसके भाई को रूस में बंधक बनाकर रखा गया है और मारपीट की गई है। बहन के मुताबिक भाई पर युद्ध में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर उसे पीटा गया और ड्रग्स के झूठे मामले में फंसा दिया गया। परिवार ने बिलासपुर कलेक्टर और एसएसपी से मिलकर सुरक्षित वापसी की मदद मांगी है। वहीं पुलिस ने रूसी दूतावास और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मदद मांगी है।

### पूरा मामला

बिल्हा के विनीत कुमार दुबे ने दसवीं तक पढ़ाई की है। परिवार के मुताबिक टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उसे रूस में नौकरी की जानकारी मिली थी। इसके बाद वह 1 अक्टूबर को मॉस्को पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि रूस पहुंचने के बाद उसे भारतीय दूतावास जाने नहीं दिया गया और मॉस्को के एक होटल में रोककर रखा गया। फिर उसे वोल्गोग्राद भेज दिया गया, जहां एक अपार्टमेंट में रखा गया।

### कार में बैठाकर ले गए, फिर संपर्क टूटा

विनीत की बहन आशी दुबे ने बताया कि 7 अक्टूबर सुबह करीब 7 बजे कुछ लोग उसे कार में बैठाकर अनजान जगह ले गए। वहां रेजिडेंसी हासिल करने और युद्ध में शामिल होने का दबाव बनाया गया। इनकार पर मारपीट की गई और भूखा रखा गया। परिवार का आरोप है कि ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर स्थानीय लोगों की बात मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। परिवार को यह जानकारी किशोर नाम के एक युवक से व्हाट्सएप के जरिए मिली।

### एसएसपी बोले- दूतावास से किया संपर्क

बिलासपुर पुलिस ने परिवार की शिकायत के बाद रूसी दूतावास और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। अब एजेंसियों के जवाब का इंतजार है। परिवार ने केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास से भी दखल देने की अपील की है। फिलहाल विनीत कहां है और उसकी हालत कैसी है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

## सुबह-सुबह खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस, 3 की मौत, 16 घायल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**बलौदाबाजार-भाटापारा।** सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। बिलासपुर से रायपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुरा के पास एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के समय बस में कुल 22 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जिन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया।

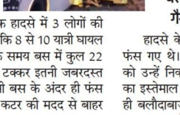

### सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक हादसा सोमवार 26 अक्टूबर सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुरा से पहले इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक खराब होने से खड़ा था। सुरक्षा के लिए ट्रक के पास स्टॉपर भी लगाया गया था। इसी दौरान अंबिकापुर से रायपुर जा रही रॉयल कंपनी की बस क्रमांक सीजी 04 एनएम 0859 खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई।

### बस में फंसे यात्रियों को गैस कटर से निकाला

हादसे के बाद कुछ यात्री बस में फंस गए थे। पुलिस और बचाव दल को उन्हें निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा।सूचना मिलते ही बलौदाबाजार पुलिस, एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को निकालकर शासकीय अस्पताल सिमगा भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त बस अंबिकापुर से रायपुर आ रही थी।

## कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, सिंहदेव बोले-वोट चोरी से लोकतंत्र खतरे में

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**अंबिकापुर।** कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तीसरे चरण के तहत अंबिकापुर में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकारवार्ता में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। सिंहदेव ने आरोप लगाया कि देशभर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का खेल चल रहा है, आयोग नियमों के विपरीत काम कर रहा है। इस दौरान एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष पटनायक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सहप्रभारी जरिता लैतफलांग भी मौजूद रहीं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक मुद्दा है जिसमें दोहरा पंजीकरण, ईवीएम-वीवीपीएटी, चुनाव संबंधी आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी शामिल है। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख मतदाता बढ़े, जिसमें से 32 लाख सिर्फ 5 महीने में जोड़े गए। बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा में 1,00,250 वोट प्रभावित होने का आरोप लगाया गया, जिसमें फॉर्म-6 का दुरुपयोग और एक ही पते पर कई वोटर शामिल हैं। पीलीभीत का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां बिना फॉर्म भरे 13 हजार मतदाताओं के नाम बदल दिए गए। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर 2026 की पड़ताल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन 30 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई वहां प्रारूप मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। देशभर में लगभग 27 लाख नाम अंतिम रूप से हटाए गए और 38 लाख अपीलें लंबित हैं। सिंहदेव ने 2023 के कानून पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस कानून ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया, जिससे संस्था की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। साथ ही धारा-16 के तहत चुनाव आयुक्तों को दिया गया कानूनी संरक्षण जवाबदेही को कमजोर करता है। इस दौरान जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता, पूर्व विधायक, रामदेव राम, शैलेंद्र प्रताप सिंह, मो. इस्लाम, इरफान सिद्दीकी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

### रैली की तैयारियों को लेकर बीएलओ की बैठक

कांग्रेस के वोट बचाओ-देश बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण और 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा और बीएलएओ की महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक देवाशीष पटनायक ने की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया गैर संवैधानिक थी। इसके जरिए देश के 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस देश विरोधी कार्य के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, देश के हर नागरिक के अधिकार की लड़ाई है।

छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लैतफलांग ने तीसरे चरण के आंदोलन की जानकारी साझा करते हुए कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जुटने का आह्वान किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह ने भी चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि देश में माहौल बता रहा है कि भाजपा साफ होने वाली है, लेकिन वह भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे चुनाव में उतरेगी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निष्फल करना है।

एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठनात्मक समीक्षा की। कांग्रेस अब सरगुजा संभाग में बूथ स्तर पर 'वोट रक्षक तैनात कर मतदाता सूची का सत्यापन करेगी और 25 नवंबर तक गांवों में चौपाल और दिल्ली चलो कार्यक्रम चलाएगी।

### स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने पर सिंहदेव ने कसा तंज

पत्रकारों के सवाल पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि, स्मृति ईरानी अगला चुनाव यहां से लड़ने वाली हैं। भाजपा में जीतने लायक स्थिति नहीं लग रही, तभी उन्हें इतना हाईलाइट किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह अंदरूनी मामला है। मैं तो स्मृति ईरानी से बस शक्कर के भाव की बात करना चाहता हूं, वो बता दें कि उन्होंने कितना शक्कर का भाव कहा था यूपी में जब वो चुनाव लड़ी थीं और आज देश में उनकी पार्टी ने कहां पहुंचा रखा है, फिर आगे की बात। सिंहदेव ने कहा कि भाजपा महंगाई के मुद्दे पर बात करने से बच रही है।

### मूल आंकड़े डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएं

एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष पटनायक ने कहा कि, वोट चोरी एक व्यापक मुद्दा है। कांग्रेस की मांग है कि मूल आंकड़े डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएं ताकि स्वतंत्र सत्यापन हो सके। कांग्रेस संबंधित रिकॉर्ड और दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। आरोप है कि, आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। 2023 के कानून ने सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। उन्होंने कांग्रेस के आगामी अभियान के बारे में विस्तार से बताया।

# समय-सीमा की बैठक : चक्रवात से निपटने की तैयारियों के साथ गिरदावरी और राज्योत्सव की हुई समीक्षा

**★ शत-प्रतिशत त्रुटिरहित गिरदावरी के कलेक्टर ने दिये निर्देश ★ फसल रिकॉर्ड की सटीकता के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय, खसरों का करेंगे भौतिक सत्यापन ★ 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' थीम पर हाई स्कूल ग्राउंड पर मनाया जायेगा राज्योत्सव**

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

**बलरामपुर।** कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आहूत की गई। बैठक में चक्रवात के प्रभाव से संभावित वर्षा, गिरदावरी कार्य तथा राज्योत्सव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है तथा कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावित स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने राजस्व अमले और आपदा प्रबंधन टीम को हर समय अलर्ट मोड पर रहकर जलभराव एवं बाढ़ की आशंका वाले संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में प्रभावितों तक तत्काल राहत पहुँचाई जाए।

कलेक्टर ने जिला एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखते हुए मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखने को कहा। राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, पंचायत, स्वास्थ्य और विद्युत सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। निचले एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर राहत एवं बचाव की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित

करने तथा एसडीआरएफ, होमगार्ड व अन्य बचाव दलों को आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार रखने को कहा गया। जलाशयों और बांधों के जलस्तर की नियमित निगरानी के साथ पानी छोड़े जाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों के लोगों को समय रहते सूचना देने पर भी विशेष जोर दिया गया। जलभराव एवं जोखिम वाले क्षेत्रों में आमजन को सतर्क करने के लिए लगातार मुनादी कराने तथा किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति की सूचना मिलने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय रहने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने को कहा।

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि नदी-नालों, जलप्रपातों और उफनते जलस्त्रोतों के पास न जाएँ तथा डूबे हुए रास्तों, पुल-पुलियों और बैरियर लगे स्थानों को पार करने का प्रयास न करें। गिरे हुए बिजली के तारों और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, बिना आवश्यकता विशेषकर रात में यात्रा से बचें तथा बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आपात स्थिति में डायल 112, जिला बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 07831-273002 अथवा स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने मौसम एवं राहत संबंधी जानकारी के लिए केवल अधिकृत स्रोतों पर भरोसा करने और अफवाहों से दूर रहने का आग्रह किया।

बैठक में गिरदावरी एवं ई-गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इसे शत-प्रतिशत त्रुटिरहित पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बहुस्तरीय सत्यापन की इस व्यवस्था से फसल रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित होगी और किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर मिल सकेगा।

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार जिले में खसरों के भौतिक सत्यापन की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत जिला, अनुभाग एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को अलग-अलग प्रतिशत में खसरों की जाँच का दायित्व सौंपा गया है। जिला स्तरीय अधिकारी आवंटित ग्रामों में 1 प्रतिशत, 5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने प्रभार क्षेत्र में 5 प्रतिशत, 19 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 10 प्रतिशत तथा 13 कृषि विस्तार अधिकारी और 23 राजस्व निरीक्षक 25-25 प्रतिशत खसरों का सत्यापन करेंगे। कलेक्टर ने सत्यापन कार्य समयबद्ध करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम व राजस्व अमले को प्राथमिकता के साथ कार्य को पूर्ण करने निर्देश दिए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की बात कही।

बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में बताया गया कि जिले में राज्योत्सव का आयोजन 02 नवंबर को हाई स्कूल ग्राउंड में किया जाएगा। इस वर्ष की थीम 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' रखी गई है, जिसके तहत लखपति दीदियों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविकामूलक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी। कलेक्टर ने कार्य विभाजन के अनुसार तैयारियों की क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, आर. एस. लाल बालेश्वर राम अभिषेक गुप्ता, सर्व एसडीएम व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

# एसईसीएल की एक खदान और वर्कशॉप में हथियारबंद चोरों का धावा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

**बिश्रामपुर।** एसईसीएल के बलरामपुर 10/12 अंडरग्राउंड खदान और बिश्रामपुर स्थित एक्रेशन वर्कशॉप में हथियारबंद चोरों ने बीती रात धावा बोलकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। आरोप है कि बड़ी संख्या में पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धारदार हथियार दिखाकर बंधक बनाया और कीमती केबल लूटकर फरार हो गए। बिश्रामपुर की वर्कशॉप में वारदात के दौरान एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया गया है। लगातार हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं से कोयलांचल के कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे बलरामपुर 10/12 अंडरग्राउंड खदान में 25 से 30 की संख्या में हथियारबंद लोग पहुंचे। आरोपियों ने सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को धारदार हथियार दिखाकर बंधक बना आर्मर्ड केबल के करीब 80 मीटर हिस्से को काटकर ले गए। बताया जा रहा है कि इसी रात करीब एक बजे बदमाशों ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया है। एक ही रात में दो बार हुई इस घटना ने खदान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलरामपुर खदान के अलावा बिश्रामपुर स्थित एक्रेशन वर्कशॉप को भी निशाना बनाया गया। यहां भी अज्ञात हथियारबंद लोगों ने सुरक्षा विभाग दो कर्मचारियों जेबीआर व मुन्ना जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर धारदार हथियार से हमला करने उपरांत लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। यहां भी आरोपियों द्वारा हजारों रुपए के कीमती केबल लूट लिए हैं। वारदात के दौरान आरोपियों ने एक्सवेशन वर्कशॉप के समीप एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ा दी है। लगातार दो स्थानों पर हुई इन वारदातों से एसईसीएल के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं।

### जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर कर्मचारी

कोयला खदानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगातार हो रही चोरी व लूटपाट की घटनाओं ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। ड्यूटी के दौरान हथियारबंद लोगों के हमले और बंधक बनाए जाने की आशंका के बीच कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए अब केवल मशीनों और उत्पादन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाना ही चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने तथा रात्रिकालीन गश्त प्रभावी बनाने की जरूरत को रेखांकित किया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रबंधन और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएंगी, ताकि वे भयमुक्त वातावरण में अपनी ड्यूटी कर सकें। ज्ञात हो कि लगातार हो रही इन वारदातों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कब और कितनी प्रभावी होगी, ताकि कोयला उत्पादन से जुड़े कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम न करना पड़े, यह भविष्य के गर्भ में है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पूर्व में भी बलरामपुर खदान में त्रिपुरा बटालियन के जवानों व बदमाशो के बीच झड़प हुई थी, उसमें भी आरोपियों द्वारा जवानों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

# बिश्रामपुर की पाखी को मिला छत्तीसगढ़ की बेस्ट ब्यूटीशियन का अवार्ड

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

**बिश्रामपुर।** हुनर, मेहनत और लगन के दम पर बिश्रामपुर की पाखी राय ने सौंदर्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। टूए कॉलोनी निवासी पाखी राय को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में छत्तीसगढ़ की बेस्ट ब्यूटीशियन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के साथ उन्हें कंपनी की ओर से चार दिवसीय सिंगापुर यात्रा का अवसर भी मिला है। वह 24 अक्टूबर को सिंगापुर के लिए रवाना हो चुकी हैं।

जानकारी के अनुसार सितंबर माह में मुंबई के आईटीसी मराठा में आयोजित इस आयोजन में देशभर से करीब 700 ब्यूटीशियन और मेकअप आर्टिस्ट शामिल हुए थे। सौंदर्य एवं मेकअप के क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों के बीच पाखी राय को छत्तीसगढ़ की बेस्ट ब्यूटीशियन के रूप में चुना जाना बिश्रामपुर के लिए गौरव की बात है। पाखी राय बिश्रामपुर की टूए कॉलोनी में पाखी ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। उन्होंने अपने काम और

कौशल के जरिए सौंदर्य सेवा के क्षेत्र में पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि ने उनके पेशेवर सफर को नई दिशा दी है। अवार्ड के साथ कंपनी की ओर से उन्हें सिंगापुर आने-जाने और वहां ठहरने सहित चार दिनों का पैकेज दिया गया है। पाखी की इस सफलता से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय स्तर पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मंच पर पहचान हासिल करना अन्य युवतियों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। पाखी के पति राजेश राय डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं। बिश्रामपुर की इस उपलब्धि ने स्थानीय प्रतिभा और मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। पाखी राय का यह सम्मान क्षेत्र में सौंदर्य व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं के लिए नई संभावनाओं और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा बन सकता है।

# बलरामपुर के हाईस्कूल ग्राउण्ड में 2 नवम्बर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा राज्योत्सव

**गरिमामयी आयोजन के लिए अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व**

**बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन।** राज्य शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में इस वर्ष जिला मुख्यालय बलरामपुर के हाईस्कूल ग्राउण्ड में 02 नवम्बर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिवसीय भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम के सफल संचालन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन द्वारा नोडल, सहायक नोडल अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशुतोष चतुर्वेदी को सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलरामपुर श्री विवेक चन्द्रा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा कंट्रोल रूम की स्थापना की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को सौंपी गई है। इसके साथ ही शासन के निर्देशानुसार 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' थीम पर आधारित सजीव प्रदर्शन, स्टॉल आबंटन, सामग्री वितरण एवं आमंत्रण पत्र का कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

राज्योत्सव स्थल पर ले-आउट निर्माण, समतलीकरण, बैरीकेटिंग, मंच निर्माण, टेंट पंडाल, पर्याप्त रोशनी और एल.ई.डी. स्क्रीन की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और विद्युत यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन द्वारा 108 एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) सहित पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था तैनात रहेगी। इसके अलावा नगर पालिका बलरामपुर द्वारा पानी टैंकर और साफ-सफाई, नगर सेना द्वारा अग्निशमन वाहन तथा जनसम्पर्क विभाग द्वारा कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार और मीडिया प्रबंधन का दायित्व निभाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मार्गदर्शन में सौंपे गए दायित्वों का समय-सीमा में निर्वहन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

# एनएच पर मौत को दावत दे रहे भूसे से ओवरलोड वाहन, दोपहिया सवारों की बढ़ी मुश्किलें

**फटे बोरों से सड़क पर उड़ता भूसा बन रहा परेशानी का सबब, आंखों में कण जाने से हादसों का खतरा**

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

**बिश्रामपुर।** राष्ट्रीय राजमार्ग-43 सहित क्षेत्र की अन्य सड़कों पर भूसे से लदे मालवाहक वाहन राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। वाहनों में असुरक्षित तरीके से भूसा लोड कर तेज रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। बोरों से निकलकर हवा में उड़ने वाला भूसा पीछे चल रहे दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल राहगीरों की आंखों, नाक और मुंह में घुस रहा है। इससे वाहन चालकों का ध्यान भटकने और संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है। व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही कभी भी गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके बावजूद भूसे का असुरक्षित परिवहन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।

### राइस मिलों से पावर प्लांट तक पहुंचता है भूसा

जानकारी के अनुसार, राइस मिलों में धान की कुटाई के बाद निकलने वाले भूसे की पावर प्लांट संचालकों द्वारा खरीद की जाती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। सूरजपुर, अंबिकापुर सहित आसपास के जिलों से भूसे का परिवहन स्थानीय स्तर पर होने के साथ ही दूसरे जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी किया जाता है। इसके लिए ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों में भूसे को बोरों में भरकर गंतव्य तक पहुंचाया जाता है।

भूसे की ढुलाई से जुड़े इन वाहनों की आवाजाही राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य प्रमुख सड़कों पर लगातार बनी रहती है। लेकिन परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। कई वाहनों में भूसे से भरे बोरे इस तरह रखे जाते हैं कि उनके फटने या उनसे भूसा बाहर निकलने की आशंका बनी रहती है। वहीं, बोरों की सिलाई कमजोर होने और उन्हें ठीक से नहीं बांधने के कारण रास्ते में

भूसा उड़ता रहता है।

### हवा में उड़ता भूसा बन रहा दुर्घटना का कारण

भूसे से लदे वाहनों के पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन की रफ्तार और हवा के दबाव के कारण बोरों से निकलने वाले भूसे के बारीक कण पीछे की ओर उड़ते हैं। ऐसे में बाइक या स्कूटी से सफर कर रहे लोगों की आंखों में अचानक भूसा चला जाता है। इससे कुछ पल के लिए सामने का रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो सकता है। चालक की नजर सड़क से हटने या संतुलन बिगड़ने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। यही स्थिति साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी पैदा करती है। खासकर व्यस्त मार्गों पर जब एक ओर भारी वाहन चल रहे हों और दूसरी ओर दोपहिया वाहन चालक उनसे आगे निकलने या सुरक्षित दूरी बनाए रखने का प्रयास कर रहे हों, तब उड़ता भूसा खतरे को और बढ़ा देता है। अचानक आंख में कण पड़ने पर चालक घबराकर वाहन मोड़ सकता है या अचानक ब्रेक लगा सकता है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने की आशंका भी बनी रहती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर आवागमन के दौरान लोगों को भारी वाहनों के बीच सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में भूसे से लदे वाहनों के पीछे चलना दोपहिया सवारों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है। कई बार वाहन चालक आगे चल रहे ट्रक से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के बावजूद हवा में उड़ते भूसे से बच नहीं पाते। इससे यात्रा के दौरान असुविधा होती है और दुर्घटना का डर बना रहता है।

लोगों का कहना है कि माल का परिवहन करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए सड़क सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यदि बोरों की सही तरीके से सिलाई की जाए, फटे बोरों को बदला जाए और भूसे को सुरक्षित तरीके से बांधकर ढुलाई की जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा, परिवहन के दौरान भूसा उड़ने से रोकने के लिए वाहनों पर उपयुक्त ढकाव की व्यवस्था भी जरूरी है।

क्षेत्रवासियों ने पुलिस और प्रशासन से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर असुरक्षित तरीके से भूसा लोड कर चलने वाले वाहनों की जांच की जानी चाहिए। जिन वाहनों से भूसा लगातार उड़ता रहता है, उनके संचालकों को सुरक्षित परिवहन के लिए निर्देशित किया जाए। साथ ही परिवहन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लोगों का मानना है कि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो किसी दिन उड़ते भूसे के कारण गंभीर सड़क हादसा हो सकता है।

# 28 अक्टूबर को विद्यालयों में मनाया जाएगा विशेष ई-कचरा प्रबंधन दिवस

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 28 अक्टूबर को विशेष ई-कचरा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार के निदेर्शानुसार ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को ई-कचरे के दुष्प्रभावों तथा उसके सुरक्षित संग्रहण एवं निपटान के प्रति जागरूक करना है। सूरजपुर जिले में कलेक्टर रेना जामिल, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा मनोज साहू के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

## 27 अक्टूबर तक होगी पूर्व तैयारी

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों में 21 से 27 अक्टूबर तक पूर्व तैयारी एवं जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस दौरान शिक्षक विद्यार्थियों और अभिभावकों को ई-कचरे के उचित प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों को अपने घरों में अनुपयोगी पड़े इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों की पहचान करने तथा उन्हें सामान्य कचरे में फेंकने के बजाय सुरक्षित तरीके से एकत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पुराने मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर, केबल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर तथा अन्य अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्यालय में एकत्रित किया जाएगा।

इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में ई-कचरा संग्रहण कॉर्नर बनाया जाएगा, जहां एकत्रित सामग्री को सुरक्षित रखा जाएगा। बाद में इसे अधिकृत ई-कचरा संग्रहकर्ता अथवा रिसायकलर को सौंपकर नियमानुसार निपटान की व्यवस्था की जाएगी।

## ई-कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती

आज के डिजिटल युग में ई-कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यदि इसका निपटान उचित तरीके से नहीं किया जाए, तो यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ई-कचरे में सीसा, पारा, कैडमियम तथा अन्य हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। इन्हें खुले में फेंकने, जलाने या अनुचित तरीके से तोड़ने पर विषैले तत्व मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। ई-कचरे को जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ा सकता है तथा दूषित मिट्टी और पानी का असर खाद्य श्रृंखला तक पहुंच सकता है। वहीं, लापरवाही से रखी गई क्षतिग्रस्त बैटरियों में रिसाव, शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी हो सकता है ।दूसरी ओर, ई-कचरे में मौजूद तांबा, एल्युमिनियम और अन्य उपयोगी धातुओं का अधिकृत प्रक्रिया से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है।

## 28 अक्टूबर को होंगी जागरूकता गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं

विशेष ई-कचरा प्रबंधन दिवस के अवसर पर विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान जागरूकता संवाद आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, नारा लेखन और चित्रकला जैसी रचनात्मक गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

# साइबर सुरक्षा की बारीकियों से रूबरू हुए कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी, साइबर सेल अंबिकापुर में लिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा तथा साइबर अपराधों की रोकथाम संबंधी व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने साइबर सेल अंबिकापुर का शैक्षणिक भ्रमण कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा की अनुमति तथा प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा एवं विभागाध्यक्ष सुश्री मोनिका खेस के मार्गदर्शन में ₹साइबर सुरक्षा जागरूकताः साइबर सेल अंबिकापुर में डिजिटल सुरक्षा और कानून का व्यावहारिक अनुभव₹ विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समन्वय सहायक प्राध्यापक उमेश पांडेय,

विनोद कुमार गुप्ता एवं अनुभव श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान रेंज साइबर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल अपराधों की पहचान, अपराध अनुसंधान की आधुनिक तकनीकों एवं बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

## एआई आधारित निगरानी प्रणाली का प्रदर्शन

साइबर विशेषज्ञ अधिकारी गणेश कदम ने विद्यार्थियों को शहर की आधुनिक निगरानी व्यवस्था, सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, फेस डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन तथा आपराधिक गतिविधियों की निगरानी की तकनीकों से अवगत कराया। उन्होंने साइबर सेल में उपयोग किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सिस्टम का व्यावहारिक प्रदर्शन किया।

## केस स्टडी के माध्यम से बताए बचाव के उपाय

उपनिरीक्षक अभय तिवारी ने विभिन्न साइबर अपराधों के उदाहरण एवं केस स्टडी के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी तथा अन्य साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक, इंटरनेट, नेटवर्किंग एवं सर्विलांस सिस्टम की सहायता से अपराधियों तक कैसे पहुंचा जाता है। विद्यार्थियों को संदिग्ध लिंक एवं कॉल से सावधान रहने तथा धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

## डायल 112 एवं हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

कंट्रोल रूम में डायल 112 के अधिकारियों ने आपातकालीन सहायता सेवा की कार्यप्रणाली, यातायात नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताया। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए 112 इंडिया ऐप एवं लोकेशन आधारित सुविधाओं के उपयोग के बारे में समझाया।

# हार-जीत से किसी की काबिलियत कम नहीं होती, खेल में भाग लेना भी बड़ी उपलब्धि - मंजूषा भगत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**26वीं राज्यस्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन, ओवरऑल चैंपियन बना रायपुर**

अंबिकापुर। खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 का समापन समारोह आज मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती मंजूषा भगत के आतिथ्य में संपन्न हुआ। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 404 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समारोह में महापौर ने विभिन्न खेल विधाओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि जीवन में हार-जीत लगी रहती है। खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर खेलना अपने आप में बड़ी

उपलब्धि है। आप सभी अपनी प्रतिभा और काबिलियत के दम पर यहां तक पहुंचे हैं। हार और जीत का अंतर किसी की काबिलियत को कम नहीं करता। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने और राष्ट्रीय प्रतिस्पधाओं में सहभागिता के लिए प्रेरित किया।

## विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों के अनुसार बैडमिंटन 17 वर्ष बालक वर्ग में दुर्ग प्रथम, रायपुर द्वितीय और बिलासपुर तृतीय स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में 17 वर्ष में दुर्ग प्रथम, रायपुर द्वितीय और सरगुजा तृतीय स्थान पर रहा। बैडमिंटन 19 वर्ष बालक वर्ग में दुर्ग प्रथम, रायपुर द्वितीय और बिलासपुर तृतीय स्थान पर रहा, जबकि बालिका वर्ग में बस्तर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और सरगुजा तृतीय स्थान पर रहा। बास्केटबॉल 14 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर ने प्रथम, सरगुजा ने द्वितीय और बिलासपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 17 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और सरगुजा तृतीय स्थान पर रहा। फुटबॉल 19 वर्ष बालक वर्ग में बस्तर ने प्रथम, सरगुजा ने द्वितीय और दुर्ग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सॉफ्ट टेनिस की विभिन्न आयु वर्गों की स्पधाओं में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 14 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, रायपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय रहा। 17 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, रायपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय रहा, जबकि 19 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और रायपुर तृतीय स्थान पर रहा। सॉफ्ट टेनिस 14 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और सरगुजा तृतीय स्थान पर रहा। 17 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, बिलासपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय स्थान पर रहा। वहीं 19 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और बिलासपुर तृतीय स्थान पर रहा।

# कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए निर्देश

**चक्रवात और भारी बारिश की चेतावनी पर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 नवंबर को**

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रताप विजय खेस्स, नगर निगम आयुक्त विनय अग्रवाल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, जन

चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायतों का गंभीरता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत वसूली प्रकरणों, अपूर्ण कार्यों, जाति प्रमाणपत्र एवं जन्म प्रमाणपत्र निर्माण, मुआवजा प्रकरणों सहित अन्य विषयों पर भी समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया कि आगामी 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का जिला आगमन प्रस्तावित है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

## मौसम विभाग की चेतावनी पर अलर्ट रहने के निर्देश

मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवात संबंधी चेतावनी एवं प्रदेश में संभावित भारी वर्षा को देखते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल की संभावना है, जिसके प्रभाव से 27 अक्टूबर को सुकमा एवं दंतेवाड़ा तथा 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में वर्षा की संभावना है। प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है ।कलेक्टर ने जिला एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, निचले इलाकों, जलभराव एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करने, एसडीआरएफ, होमगार्ड को तैयार रखने तथा जलाशयों और बांधों के जलस्तर की सतत निगरानी के निर्देश दिए।

## राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 नवंबर को

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर 2026 को प्रस्तावित एक दिवसीय राज्योत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन हेतु सभी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आवागमन, स्टॉल, साफ-सफाई, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, मंच एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

# सरगुजा में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान, अंबिकापुर से रायपुर-जगदलपुर होते हुए हैदराबाद तक उड़ान शुरू

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के लोगों के लिए हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के बाद अब अंबिकापुर से रायपुर और रायपुर से जगदलपुर होते हुए हैदराबाद तक हवाई यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। इस हवाई सेवा के शुरू होने से सरगुजावासियों को आवागमन का एक नया विकल्प मिलेगा और प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस मार्ग पर एटीआर-72 विमान के माध्यम से हवाई सेवा उपलब्ध कराने की पहल के लिए एलायंस एयर का आभार जताया गया है। नई सेवा की शुरूआत को सरगुजा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए

क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं।

## मंगलवार को पहली उड़ान से रवाना होंगे जनप्रतिनिधि

हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर संबंधित जनप्रतिनिधि ने मंगलवार को इसी फ्लाइट से अंबिकापुर से रायपुर के लिए रवाना होने की जानकारी दी है। इससे नई हवाई सेवा की शुरूआत को लेकर क्षेत्र में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।

## लंबे समय से थी मांग

अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू होना सरगुजा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है। इस सुविधा से यात्रियों को सड़क मार्ग पर लगने वाले समय से राहत मिलेगी। साथ ही, कारोबार, पर्यटन, चिकित्सा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा ।अंबिकापुर को रायपुर, जगदलपुर और हैदराबाद से जोड़ने वाली यह हवाई सेवा क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।

# संभाग स्तरीय फुटबॉल मुकाबले मे सरगुजा इलेवन और परसोड़ी सेमीफाइनल में

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। गांधी स्टेडियम में चल रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले जा रहे सुपर लीग मुकाबलों में दो अहम मैच खेले गए, जिनके बाद सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई। फुटबॉल प्रेमियों की भारी मौजूदगी के बीच खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। सुपर लीग का पहला मैच रेलवे करंजी और परसोड़ी के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने मैदान पर संतुलित और रक्षात्मक खेल दिखाया। प्रथम हाफ में दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर

कई हमले किए, अच्छे पास और तालमेल देखने को मिला, लेकिन गोलकीपरों की मुस्तैदी और डिफेंस की मजबूती के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में भी मैच का रोमांच बरकरार रहा, दोनों टीमों ने गोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन स्कोर बोर्ड 0-0 ही रहा। नियमानुसार दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया गया। इस अंक के साथ परसोड़ी टीम ने अंक तालिका में कुल 5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दिन का दूसरा और सबसे रोमांचक मैच सरगुजा इलेवन और मेंडरा के बीच खेला गया। इस मैच में सरगुजा इलेवन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। प्रथम हाफ में सरगुजा इलेवन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और एकतरफा खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने लगातार हमले करते हुए विपक्षी डिफेंस को पूरी तरह से बिखेर दिया और 5 गोल दागकर 5-0 की बड़ी बढ़त बना ली। दर्शकों ने हर गोल पर तालियों से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। दूसरे हाफ में मेंडरा की टीम ने वापसी की कोशिश की और दोनों टीमों ने तेज और रोमांचक खेल दिखाया। दोनों तरफ से लगातार हमले हुए, कई सुनहरे मौके भी बने, लेकिन दूसरे हाफ में कोई गोल नहीं हो सका। अंततः सरगुजा इलेवन ने 5-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया ।मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष जीतेन्द्र गुप्ता जीतू उपस्थित रहे।

उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैच के निर्णायक के रूप में ललित किशोर, सचिन, सुशील, शिव बहादुर लाम्बा ने भूमिका निभाई। इस अवसर पर आयोजन समिति के सचिव दीपक कुजूर, कमलेश किस्पोट्टा सहित कई खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज प्रतियोगिता का प्रथम सेमीफाइनल मैच दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा। यह मुकाबला बलसेड़ी और परसोड़ी के बीच होगा। दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी।

# प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु चयन सूची जारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय (घंघरी) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चतुर्थ ओपन काउंसलिंग में प्राप्त आवेदनों के आधार पर चतुर्थ चयन सूची जारी कर दी गई है। चयन सूची मेरिट क्रम के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निदेर्शानुसार चयनित विद्यार्थियों को 30 अक्टूबर तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) से उत्तीर्ण अंकसूची, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विशेष पिछड़ी जनजाति प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश की पात्रता होने पर दो दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी से काउंटर हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) एवं जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित विद्यार्थियों को आवंटित प्रयास आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश लेना होगा। विद्यालय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

## आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती हेतु अंतिम सूची जारी, 5 नवम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

अम्बिकापुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) के परियोजना अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के 01 पद आंगनबाड़ी केन्द्र खालपारा वार्ड क्रमांक 06 में भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसकी अंतिम सूची प्रकाशन कर विभागीय वेबसाइट द्वारा आनलाईन दावा आपत्ति 26 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक आंमत्रित की गई है। निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।

**फ्रांस में अंजाम दी गई बेरोक-टोक अग्निकांडों और लूटपाट की वारदातों से समूची दुनिया स्तब्ध होकर रह गई है। आखिरकार इस विनाशकारी हिंसक आंदोलन की बुनियाद में कौन से प्रमुख कारण विद्यमान रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हिंसक वारदातों के लिए फ्रांस के इस्लामी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इसके पीछे अल्ट्रा लेफ्ट ताक़तों को जिम्मेदार मानते हैं। इस हिंसक विरोध आंदोलन की कड़ियां भारत तक जुड़ गई हैं। इसमें विदेशी संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल सरकारों की नीतियों का विरोध करना है या चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना भी है? इन सवालों ने हाल ही में अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज की एक खोजी रिपोर्ट के बाद चर्चा का रूप ले लिया है। यूरोप के हिंसक प्रदर्शनों से भारत को सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों के भरोसे, संस्थाओं की निष्पक्षता, शांतिपूर्ण असहमति की स्वतंत्रता और कानून के समान अनुपालन में निहित है। भारत ने जिस तरह से हालिया प्रदर्शनों को नियंत्रित किया है, उस पर टिप्पणी को लेकर मानवाधिकार संगठनों का छद्म छलावा प्रदर्शित होता है।** ***इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...***

# फ्रांस से उठा यूरोप में फैला हिंसक तूफान

**विश्लेषण**

प्रभात कुमार राय

विदेश मामलों के जानकार

**16 सितंबर 2026 का दिन था। पेरिस से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव का एक हाई स्कूल, जहां से फ्रांस में विद्यार्थियों के वर्तमान आंदोलन की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों की दीर्घ काल से सरकार से मांग रही है कि उनके स्कूल में पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं हैं और स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। आखिरकार विद्यार्थियों द्वारा अपने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक स्कूल से शुरू हुआ विद्यार्थी आंदोलन आसपास के स्कूलों में तेजी के साथ फैल गया, क्योंकि तकरीबन सभी स्कूलों के हालात बहुत ही खराब रहे हैं। इन स्कूलों के अध्यापक भी विद्यार्थियों के आंदोलन में शामिल हो गए और उनके मेहनतकश मां-बाप भी धीमे-धीमे इसमें शामिल होने लगे। कुछ ही दिनों में आंदोलन तेजी से फ्रांस में विस्तारित हो गया।**

संपूर्ण दुनिया स्तब्ध होकर रह गई है, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस और आसपास के नगरों की सार्वजनिक इमारतों से उठती हुई विनाशकारी अग्नि ज्वालाओं का दुनिया ने दीदार किया। फ्रांस में अंजाम दी गई बेरोक-टोक अग्निकांडों और लूटपाटों ने फ्रांस का ही नहीं, वरन् समूची दुनिया के दिल को हिला कर रख दिया है। इंतहा तो तब हो गई, जब पेरिस से उठा हिंसककारी आंदोलन अल्बानिया, इटली, स्पेन, सर्बिया आदि यूरोप के अनेक देशों में भी फैल गया है। आखिरकार इस विनाशकारी हिंसक आंदोलन की बुनियाद में कौन से प्रमुख कारण विद्यमान रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ्रांस में अंजाम दी गई हिंसक वारदातों के लिए फ्रांस के इस्लामी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। ट्रंप ने अपने मतदाताओं को खबरदार करते हुए फरमाया कि बस आप फ्रांस को देख लीजिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्रांस का पेरिस नगर बहुत जल्दी एक मुस्लिम बहुल नगर बन जाएगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को बेहूदा और एकदम गलत बताया। यह कहना कि फ्रांस के इस्लामी प्रवासियों की भारी भीड़ ने फ्रांस पर हमला किया है, डोनाल्ड ट्रंप की यह बात पूरी तरह से बेबुनियाद और सरासर झूठ है। मैक्रों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के लिए हमारे देश के विद्यार्थी आंदोलन के विषय में एकदम झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस में हिंसक वारदातों के लिए फ्रांस की अल्ट्रा लेफ्ट ताक़तें जिम्मेदार हैं। 16 सितंबर 2026 का दिन था। पेरिस से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव का एक हाई स्कूल, जहां से फ्रांस में विद्यार्थियों के वर्तमान आंदोलन की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों की दीर्घ काल से सरकार से मांग रही है कि उनके स्कूल में पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं हैं और स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। आखिरकार विद्यार्थियों द्वारा अपने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक स्कूल से शुरू हुआ विद्यार्थी आंदोलन आसपास के स्कूलों में तेजी के साथ फैल गया, क्योंकि तकरीबन सभी स्कूलों के हालात बहुत ही खराब रहे हैं।

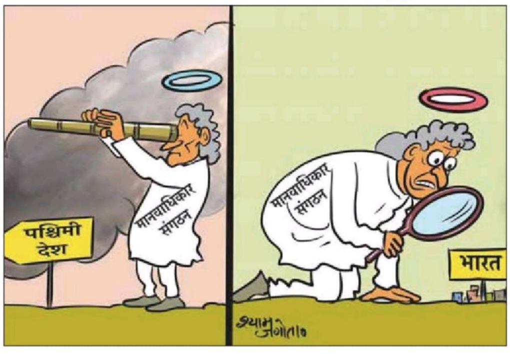


## फ्रांस में आपातकाल घोषित होने के आसार

वामपंथी शक्तियां बेहद खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई को इस अत्यंत हिंसक आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। 17 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रदर्शन स्थल प्लाजा द ला रिपब्लिक पर तकरीबन आठ लाख लोग वस्तुतः बढ़ती हुई महंगाई और अच्छी सरकारी शिक्षा के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। किंतु काले कपड़ों में कुछ नकाबपोश एक्टिविस्टों के एक गिरोह के आने के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन अत्यंत हिंसक हो उठा। अभी तक तकरीबन पांच हजार उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री लेकोर्नो द्वारा भयानक हिंसा के लिए अल्ट्रा लेफ्ट के एक्टिविस्टों को दोषी करार दिया गया है। भयानक हिंसा के तांडव तत्पश्चात राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा बयान जारी किया गया कि फ्रांस में आपातकाल नाफिज किया जा सकता है। फ्रांस के गृहमंत्री लारा न्युनेज ने कहा है कि पेरिस के अनेक नगरों में हिंसक विरोधी प्रदर्शन के बाद हालात दंगा नियंत्रक पुलिस के नियंत्रण से बाहर निकल गए। गृहमंत्री द्वारा भी हिंसक दंगों के लिए अल्ट्रा लेफ्ट के एक्टिविस्टों को दोषी करार दिया गया है। फ्रांस में प्रदर्शनों का दौर जारी है। राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है।

## 6 माह बाद फ्रांस में होंगे चुनाव

ये सभी मेहनतकश किसानों और मजदूरों के बच्चों के सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों के अध्यापक भी विद्यार्थियों के आंदोलन में शामिल हो गए और उनके मेहनतकश मां-बाप भी धीमे-धीमे इसमें शामिल होने लगे। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों में हाई स्कूल के विद्यार्थियों का आंदोलन बहुत तेजी के साथ संपूर्ण फ्रांस में विस्तारित हो गया। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के आंदोलन में फ्रांस की यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी भी शामिल होने लगे और अमीरों के स्कूलों के विद्यार्थी भी इस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए सड़कों पर आ गए। फ्रांस के मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स भी आंदोलन में शामिल हो गई। विद्यार्थी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए दंगा नियंत्रक पुलिस फोर्स भेजी गई। क्योंकि ये कहीं-कहीं आंदोलन हिंसक होने लगा था। उल्लेखनीय है कि अगले वर्ष 6 महीनों के बाद फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला वामपंथी और दक्षिणपंथी उम्मीदवारों के बीच होना है। राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार हैं प्रवासी विरोधी अति राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी मरीन ले पेन और पूंजीवाद के घोर विरोधी वामपंथी उम्मीदवार जीन ल्यूक मेलेंचोन।

## राजनीतिक दल भी शामिल

फ्रांस के राजनीतिक दल भी इस हिंसक बन चुके आंदोलन में शामिल होकर अपने-अपने लिए सुर्खियां बटोरने की होड़ में जुटे हुए हैं। इस वक्त फ्रांस में हिंसक तांडव अत्यंत तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। फ्रांस के आंदोलन में जारी भयानक आगजनी और हिंसक तांडव फ्रांस के वर्तमान इतिहास में सबसे खराब घटनाओं में से एक रहा है। फ्रांस में हिंसक तनाव राजनीति के गलियारों से लेकर सड़कों तक तांडव करता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मुख्यालय एलिसी पैलेस के अनुसार देश के गृहमंत्री लॉरेंट न्युनेज ने अपना त्यागपत्र देने की पेशकश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया और फरमाया कि फ्रांस की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए और भयानक हिंसा के दोषी अपराधियों को इंसाफ के कठघरे में लाने के लिए सख्त तौर तरीके अख्तियार किए जाएं। फ्रांस की हुकूमत के मुताबिक तकरीबन दो हजार दुकानों और व्यवसायों में आगजनी और लूटपाट अंजाम दी गई है। दंगा नियंत्रक पुलिस द्वारा हिंसक भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। वाटर कैनन की बौछारें की गई। जगह-जगह पर पुलिस को उपद्रवी भीड़ को लाठियां से पीटते हुए देखा गया।

## मैक्रों की नीतियों की आलोचना

कहीं भी फ्रांस की दंगा नियंत्रक पुलिस द्वारा हिंसक उपद्रवियों पर गोलियां नहीं दागी गई। सिर्फ एक व्यक्ति के हताहत होने का समाचार है। फ्रांस के गृहमंत्रालय के अनुसार 17 अक्टूबर को लगभग एक हजार पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए। जिसमें सात की हालत बहुत गंभीर है। विश्व पटल पर प्रख्यात पर्यटक सिटी ऑफ लाइट पेरिस में आजकल दुर्भाग्यवश अंधकार छाया हुआ है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा पेरिस के कुछ हिस्सों में और कुछ अन्य शहरों में कर्फ्यू नाफीज कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रों ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता और शांति बनाए रखने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्वारा फ्रांसीसी जनता को आश्वासन देने का प्रयास किया गया कि हिंसा के दोषियों को कानून द्वारा कठोरतापूर्वक दंडित किया जाएगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की नीतियों की जमकर आलोचना भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके शासनकाल के दौरान फ्रांस के हालात बद से बदतर होते गए हैं। फ्रांस की दक्षिणपंथी शक्तियां मध्यमार्गी राष्ट्रपति मैक्रों की फ्रांसीसी हुकूमत को उसकी विनाशकारी प्रवासी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं

# एकांगी दृष्टिकोण के असर में मानवाधिकार संगठन

**दिखावा**

उमेश चतुर्वेदी

राजनीतिक समीक्षक

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब भारतीय सुरक्षा बलों और सरकार पर उसकी कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाया हो। कश्मीर घाटी में आतंकी खून बहाते रहे, तब मानवाधिकार संगठनों ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब भी इन आतंकियों के खिलाफ भारतीय बलों ने कड़ी कार्रवाई की, उनके समर्थकों को सीखचों के पीछे डालना शुरू किया, मानवाधिकार संगठनों को उनके मानवाधिकार की चिंता होने लगी। ऐसे में हालिया आंदोलनों के दौरान भारत सरकार की कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठन सवाल नहीं उठाते तो ही हैरत होती। नीट परीक्षा के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के बीस जुलाई के संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, उसके खिलाफ अगर सुरक्षा बल, ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो बाद में वे ही सवालों के घेरे में होते। संसद से महज दो सौ मीटर की दूरी पर जिस तरह आंदोलन में शामिल असामाजिक और अराजक तत्त्व उकसाऊ कार्रवाई कर रहे थे, उसमें पुलिस और प्रशासन के पास बल प्रयोग के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। सोचिए अगर, उस दिन उपद्रवी संसद में घुस जाते और भारतीय संसद के साथ कुछ वैसी ही अनहोनी होती, जैसा अभी हालिया प्रदर्शन के दौरान अल्बानिया में हुआ है तो क्या भारतीय लोकतांत्रिक समाज उसे स्वीकार कर पाता? भारत में हालिया आंदोलनों की शुरूआत नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में हुई। इसी दौरान अचानक से एक नई पार्टी 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनी और उसके बैनर तले देशभर के युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डाल दिया। मर्यादित आंदोलनों के जरिए लोक अपना गुस्सा निकालकर शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लोक में अराजक तत्त्व भी होते हैं और वे आंदोलनों की ताक में रहते हैं। लोकतांत्रिक आंदोलनों में वे मौका पाते ही घुस जाते हैं और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बीस जुलाई के संसद में मार्च में ऐसा ही हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में ऐसा ही हुआ। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने में जेनुइन छात्रों की संख्या कम, अराजक और असामाजिक तत्वों की संख्या ज्यादा रही। इस तथ्य को सुरक्षा बलों ने भी स्वीकार किया है। सुरक्षा बलों के नरम रूख के पीछे आंदोलन में शामिल युवा रहे। सुरक्षा बलों और प्रशासन को लगता था कि अगर युवाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन एसआईआर के खिलाफ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की ओर बढ़ा, इसने राजनीतिक रंग ले लिया। निश्चित तौर पर इस पूरे आंदोलन में छात्र कहीं नेपथ्य में जाते हुए दिखे और मोर्चे पर कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दल दिखे। सुरक्षा बलों ने अपना संयम बनाए रखा। चुनाव आयोग पर प्रदर्शन के लिए संसद से निकले विपक्षी सांसदों और उनके समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। लोगों को जुटने से रोका गया। हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हुई हो, किसी को चोट लगी हो। आंदोलन में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। दुनिया की कोई भी सरकार आंदोलनकारियों का फूलों से स्वागत नहीं करती। सरकार और सुरक्षा बलों ने जिस तरह संयम दिखाकर सिर्फ हिरासत में लेकर आंदोलन को हिंसक होने से रोकने में सफलता पाई, उसका समाज के एक बड़े हिस्से ने स्वागत भी किया है। आंदोलनकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता को आसानी से भाजपा का एजेंट कहा जा सकता है। लेकिन त्योहारी मौसम में कारोबारी नुकसान पहुंचा रहे कनॉट प्लेस के कारोबारियों का आंदोलन के विरोध में खड़ा होना मामूली बात नहीं है। इससे साफ हुआ कि जनता भी ऐसे आंदोलनों को पसंद नहीं कर रही। दुर्भाग्य यह है कि चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर ह्यूमनराइट वाच, या संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम, सुरक्षा बलों के संयम, प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की ओर ध्यान नहीं दिया। एसआईआर और नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ हुए आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति एवं विशेषज्ञों का चिंता जताना मामले का एक तरफा संज्ञान लेना है। ह्यूमन राइट्स वॉच और संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएनसीईआरडी ने अपनी रिपोर्टों में, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने और उनके खिलाफ नफरती भाषण आदि का आरोप लगाया है। ये संगठन विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी एफसीआरए और कड़े आतंकवाद-विरोधी कानूनों, मसलन यूएपीएके दुरुपयोग का भी भारत पर आरोप लगाते रहे हैं। मानवाधिकार संगठन चाहे जो भी कहें, लेकिन विशेषकर राजधानी दिल्ली में जिस तरह सुरक्षा बलों ने खुद पर हुए हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाई में संयम दिखाया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। पश्चिमी समाज और उसके कथित मानवाधिकार संगठनों का नजरिया विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के लिए एकतरफा ही रहा है। बेशक भारत आर्थिक रूप से दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन अब भी भारत को लेकर उनकी सोच पुरानी ही है। जिसे अब देश की अधिसंख्य जनता समझने लगी है, इसीलिए अब ऐसे आरोपों और पर्यवेक्षणों से भारतीय मानस उस तरह प्रभावित नहीं होता, जैसा अतीत में होता रहा है।

**ह्यूमन राइट्स वॉच व संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएनसीईआरडी ने अपनी रिपोर्टों में, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने और उनके खिलाफ नफरती भाषण आदि का आरोप लगाया है।**

# विरोध-प्रदर्शनों के पीछे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

**रिपोर्ट**

विवेक शुक्ला

वरिष्ठ पत्रकार

दुनिया के अलग-अलग देशों में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के बीच क्या कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी काम कर रहा है? क्या कुछ विदेशी संगठन स्थानीय असंतोष को साझा राजनीतिक अभियान का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल सरकारों की नीतियों का विरोध करना है या चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना भी है? इन सवालों ने हाल ही में अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज की एक खोजी रिपोर्ट के बाद चर्चा का रूप ले लिया है।

रिपोर्ट में फ्रांस में छात्र आंदोलनों और भारत में हुए राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के बीच कथित संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें इंडियन एलायंस पेरिस (आईएपी) नामक संगठन का भी जिक्र है। हालांकि, रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है। फॉक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विभिन्न देशों में सक्रिय 101 संगठन विरोध-प्रदर्शनों के आयोजन, उनके प्रचार या उनके संदेशों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में जुड़े हुए हैं। इस कथित नेटवर्क में वामपंथी और समाजवादी समूहों, छात्र संगठनों, श्रमिक संघों, मीडिया मंचों तथा राजनीतिक सक्रियता से जुड़े संगठनों की भूमिका है। इस दावे का आधार यह है कि अलग-अलग देशों में होने वाले आंदोलनों के बीच सोशल मीडिया संदेशों, सार्वजनिक बयानों, संगठनों के आपसी संपर्क और एकजुटता अभियानों के माध्यम से संबंध बनते दिखाई देते हैं। फ्रांस में छात्रों के आंदोलनों और भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों का संदर्भ इसी सिलसिले में सामने आया है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या विरोध-प्रदर्शनों के बीच वैचारिक समानता, साझा संदेश या अंतरराष्ट्रीय समर्थन अपने आप में किसी गुप्त साजिश का प्रमाण है? ऐसे संबंध किसी संगठित राजनीतिक अभियान की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं, लेकिन उनसे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि संबंधित संगठन किसी चुनी हुई सरकार को गिराने या विरोध-प्रदर्शन शुरू कराने की योजना चला रहे हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में इंडियन एलायंस पेरिस को फ्रांस में सक्रिय भारतीय मूल के छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों से जुड़ा संगठन बताया गया है। इस संगठन ने फ्रांस प्रदर्शनों से संबंधित संदेशों को सोशल मीडिया पर साझा किया और भारत तथा फ्रांस में युवाओं के आंदोलनों के बीच समानताओं को रेखांकित किया। रिपोर्ट में न्यूयॉर्क स्थित पीपुल्स फोरम और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मंच प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का भी उल्लेख किया गया है। इन संगठनों और कुछ अन्य समूहों के बीच संपर्कों को आधार बनाकर यह सवाल उठाया गया है कि क्या अलग-अलग देशों के आंदोलनों को साझा राजनीतिक दिशा देने की कोशिश हो रही है। इंडियन एलायंस पेरिस का नाम सामने आने से भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हुई है। हालांकि, किसी संगठन का दूसरे संगठनों के साथ कार्यक्रम आयोजित करना, किसी आंदोलन का समर्थन करना या सोशल मीडिया पर संदेश साझा करना अपने आप में गैरकानूनी गतिविधि अथवा सरकार गिराने की साजिश का प्रमाण नहीं है। इसके लिए वित्तीय लेन-देन, निर्देशों, संगठनात्मक नियंत्रण और वास्तविक गतिविधियों से जुड़े ठोस साक्ष्यों की जरूरत होती है। इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू विदेशी वित्त पोषण है। रिपोर्ट में अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम और उनसे जुड़े कुछ संगठनों का उल्लेख किया गया है। इस विषय पर विचार करते समय लोकतंत्र के दो बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। पहला, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए विदेशी धन, गुप्त निर्देशों या गैरकानूनी हस्तक्षेप का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। यदि ऐसे हस्तक्षेप के प्रमाण मिलते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। आवश्यक है कि किसी भी रिपोर्ट में किए गए दावों की जांच दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड, प्रत्यक्ष साक्ष्यों और संबंधित संगठनों के जवाबों के आधार पर की जाए। यह भी देखना चाहिए कि संगठनों के बीच संबंध केवल वैचारिक समर्थन और प्रचार तक सीमित हैं या वास्तव में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए निर्देशित गतिविधियां संचालित की गई हैं।

**इंडियन एलायंस पेरिस का नाम सामने आने से भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हुई है। हालांकि, किसी संगठन का दूसरे संगठनों के साथ कार्यक्रम आयोजित करना, किसी आंदोलन का समर्थन करना अपने आप में गैरकानूनी गतिविधि अथवा सरकार गिराने की साजिश का प्रमाण नहीं है।**

# समय पर संवाद और समाधान जरूरी

**मंथन**

योगेश कुमार सोनी

स्वतंत्र पत्रकार

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज बुलंद करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जब सरकारें जनभावनाओं को अनसुना करती हैं, नीतियों से असंतोष बढ़ता है या लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तब सड़कों पर उतरकर विरोध करना स्वाभाविक है। जब यही विरोध हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से टकराव का रूप ले लेता है, तो सवाल केवल प्रदर्शनकारियों के उद्देश्यों का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और कानून के शासन का भी बन जाता है। यूरोप के विभिन्न देशों में समय-समय पर हुए हिंसक प्रदर्शनों से भारत को भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। हालांकि यूरोप एक समान राजनीतिक या सामाजिक इकाई नहीं है।

फ्रांस में पेंशन सुधारों के विरोध, किसानों के आंदोलन, ब्रिटेन में दंगों और अन्य देशों में आर्थिक असंतोष से जुड़े प्रदर्शनों की परिस्थितियां अलग-अलग रही हैं। इसलिए हर घटना को एक ही नजरिये से देखने के बजाय उसके कारणों और परिणामों को समझना आवश्यक है। हिंसक प्रदर्शनों का पहला सबक यह है कि जन-असंतोष को समय रहते समझना और उसका समाधान करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, किसानों की समस्याएं, सामाजिक भेदभाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा जैसे मुद्दे लोगों में नाराजगी पैदा कर सकते हैं। यदि नागरिकों को लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहरा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण है। यहां भाषाई, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और आर्थिक विविधता के कारण अलग-अलग वर्गों की अपेक्षाएं भी अलग हैं। सरकारों को चाहिए कि वे नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में जनसंवाद को प्राथमिकता दें। समय पर संवाद और शिकायतों का समाधान कई बार उस स्थिति को पैदा होने से रोक सकता है, जिसमें सामान्य विरोध उग्र हो जाता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर हिंसक घटना का कारण सरकारी नीतियों की विफलता ही नहीं होता। अफवाहें, संगठित उकसावे, आपराधिक तत्व और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी परिस्थितियों को बिगाड़ सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि नागरिक सरकार की नीतियों से असहमति जता सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना, जुलूस और सार्वजनिक बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं। लेकिन किसी नीति का विरोध करने का अधिकार सार्वजनिक संपत्ति जलाने, दुकानों को लूटने, वाहनों में आग लगाने या आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में डालने का अधिकार नहीं बन जाता। यूरोप की हिंसक घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि जब विरोध की सीमा टूटती है, तो सबसे अधिक नुकसान अक्सर उन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हितों की रक्षा का दावा किया जाता है। कारोबार प्रभावित होता है, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, छोटे दुकानदारों की आजीविका पर असर पड़ता है और भय का वातावरण बनता है। सोशल मीडिया जनसमस्याओं को सामने लाने, लोगों को संगठित करने और प्रशासन तक शिकायतें पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। लेकिन यही माध्यम भ्रामक सूचनाओं, पुराने वीडियो को नई घटना बताकर प्रसारित करने, नफरत फैलाने और भीड़ को उकसाने का जरिया भी बन सकता है। यूरोप और भारत, दोनों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में बिना पुष्टि की गई खबरें आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। नागरिकों को किसी भी संदेश या वीडियो को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए।

यूरोप के हिंसक प्रदर्शनों से भारत को सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों के भरोसे, संस्थाओं की निष्पक्षता, शांतिपूर्ण असहमति की स्वतंत्रता और कानून के समान अनुपालन में निहित है। आखिरकार किसी भी आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, उसे हिंसा और अराजकता के हवाले करना नहीं।

**यूरोप की हिंसक घटनाएं याद दिलाती हैं कि जब विरोध की सीमा टूटती है, तो सबसे अधिक नुकसान अक्सर उन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हितों की रक्षा का दावा किया जाता है। कारोबार प्रभावित होता है, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, छोटे दुकानदारों की आजीविका पर असर पड़ता है।**

## खबर संक्षेप

### आंध्र में 100 शहरी निकाय चुनाव रुका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोगने 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 13 नगर निगमों तथा 87 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव की कार्रवाई रोक दी गई। टीडीपी-वाइएसआरसीपी के बीच जारी हिंसक झड़पों के बीच कोर्ट ने यह कदम उठाया।

### कन्नड़ लोगों को नौकरी नहीं तो होगी कार्रवाई

बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर निजी संस्थान राज्य में कन्नड़ लोगों को जानबूझकर नौकरी के अवसर नहीं देते हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी। कन्नड़ लोगों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार के अवसरों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अधिकारों, सम्मान और अवसरों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

### दशकर्म में झड़प, पीके के सामने चले लाठी-डंडे

वैशाली। जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की रामपुर श्यामचंद पंचायत के भगतान टोला में शनिवार को 13 बच्चों के दशकर्म कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प हो गई। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मौजूदगी में दो पक्षों में मारपीट में सत्तारूढ़ जदयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव गंभीर रूप से

घायल हो गए। उनके सिर में चोट आई है।

### यूपी में वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वाल्मीकि जयंती देशभर में 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

---

### प्रधानमंत्री ने ओडिशा में आरबीआई के डेटा सेंटर का किया उद्घाटन

# विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता, वित्तीय सेवाएं अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रभावी होंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भुवनेश्वर के जटनी (इन्फो वैली-2) में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 169 करोड़ रुपए के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास का विस्तार ही हमारी प्राथमिकता है। साथ ही ये भी कहा कि भारत में अब गवर्नेंस की भूमिका बदल रही है।

### *देश का विकास तभी संतुलित होगा, जब गांवों और छोटे शहरों को भी पर्याप्त अवसर मिलेंगे*

एजेंसी ▶▶ भुवनेश्वर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। करीब 169 करोड़ से तैयार इस सुविधा को देश की डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास है और विकास का लाभ गांवों, छोटे शहरों तथा समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित, सक्रिय प्रशासन और सुशासन के मॉडल पर काम कर रही है। देश का विकास तभी संतुलित होगा, जब गांवों और छोटे शहरों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यह नया केंद्र डिजिटल वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इससे बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को संचालित करने के लिए सुरक्षित तकनीकी आधार मिलेगा।

आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री

#### ओडिशा को दी बड़ी सौगात

#### जटनी स्थित इन्फो वैली-2 में बनाया गया, 18.55 एकड़ क्षेत्र में बना

आरबीआई का यह केंद्र ओडिशा के जटनी स्थित इन्फो वैली-2 में बनाया गया है। यह 18.55 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसकी आधारशिला 22 मार्च 2023 को तत्कालीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रखी थी। इस परिसर में डेटा सेंटर के साथ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी है। यहां महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणालियों के साथ अन्य प्रमुख तकनीकी पहलों का संचालन किया जाएगा। डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ बैंकिंग व्यवस्था में डेटा की सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। यह केंद्र वित्तीय आंकड़ों और तकनीकी प्रणालियों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

#### डिजिटल बैंकिंग ने चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने देश के लोगों को चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि अब ऐसे लोग भी बैंक से सस्ता और आसान कर्ज ले सकते हैं, जिनके पास गारंटी देने के लिए संपत्ति नहीं है।

**वित्तमंत्री सीतारमण ने भी किया संबोधित**

### प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों को दी कर्ज की सुविधा, लोग लाभान्वित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों के लिए बैंक से कर्ज लेना आसान बनाया है। सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए 60 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण खातों में 43 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है।

#### अब देश में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले

सीतारमण ने बताया कि 2014 में हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। उनके अनुसार अब देश में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इन खातों में सालाना शुल्क और न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त नहीं है।

**डेटा सेंटर डिजिटल युग की तिजोरी के समान:** डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ा है। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। वित्त मंत्री ने डेटा सेंटर को डिजिटल युग की तिजोरी जैसा बताया। सरकार ने 2022 में डेटा सेंटर को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया था।

#### वित्तीय सेवाओं की होगी बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में मौजूद डेटा सेंटरों से वैश्विक क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए कर छूट की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

#### कार्यक्रम में ये रहे शामिल

कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम, सीएम मोहन चरण माझी, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम और उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव भी थे।

---

#### पीएम मोदी का वाराणसी में स्वागत

### उमड़ा जनसैलाब, 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजा नमो घाट

**वाराणसी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रविवार को वाराणसी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस लाइन से नमो घाट तक करीब सात किलोमीटर लंबे मार्ग पर लोगों ने पुष्प वर्षा, ढोल-नगाड़ों और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से अपने काफिले के साथ नमो घाट पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय वायुसेना के एयर शो में शामिल होना है।

- हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन

इस दौरान लोगों में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्रीका काफिला पुलिस लाइन से सांस्कृतिक संकुल, चौकाघाट, कज्जाकपुरा और राजघाट पुल होते हुए नमो घाट पहुंचा। मार्ग में जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए थे और बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के दोनों ओर खड़े होकर उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। भदऊचुंगी समेत कई स्थानों पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री ने कुछ स्थानों पर वाहन से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन किया। इस दौरान उनके काफिले पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं और देशभक्ति गीतों के साथ स्वागत किया गया।

#### 'नमो-नमो' का उद्घोष किया

नमो घाट पहुंचने पर वायु सेना के अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गंगा तट पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर 'नमो-नमो' के उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत के लिए जुटे लोगों में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल रहे। घाटों और आसपास के इलाकों में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री खोचवां में अरविंद मिल लिमिटेड की नई टेक्सटाइल इकाई का उद्घाटन कर चुके हैं। 7 एकड़ में स्थापित इकाई में परिधानों का उत्पादन किया जाएगा।

---

#### अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन खत्म

### मंत्री खट्टर ने शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया

एजेंसी ▶▶ भुवनेश्वर

19वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 रविवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री, श्री मनोहर लाल ने समापन सत्र को संबोधित किया और शहरी परिवहन में उत्कृष्टता तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। 23-24 अक्टूबर को सम्मेलन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आयोजित किया गया था। समापन सत्र में ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव उषा पाधी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी परिवहन विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए।

#### नीति आयोग ने विकास पर दिया जोर

### हम राज्य की राजधानियों से शहरों को नहीं चला सकते

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शहरी प्रशासन, योजना और वित्तपोषण में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत में चल रहे जनसांख्यिकीय और शहरी बदलाव के व्यापक दायरे पर जोर देते हुए गौबा ने बताया कि भारत की जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी और 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर स्थिर हो जाएगी।

2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है, जिससे शहरी जनसंख्या 85 करोड़ होने का अनुमान है। शहरी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने शहरों की योजना बनाने, प्रशासन और वित्तपोषण के तरीकों में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी।

#### ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर विवाद पर कांग्रेस का सवाल

### कांग्रेस नेता जयराम ने कहा | जानकारी क्यों छिपा रहा चुनाव आयोग? सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर विवादित ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि आयोग जानकारी को सार्वजनिक करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि इससे एसआईआर प्रक्रिया में कथित तौर पर हुई बड़े पैमाने की और केंद्रीकृत गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सकती है। विपक्षी दल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर रिपोर्ट साझा की। रिपोर्ट में दावा कियाईसीआई ने ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के नाम और उसके संस्करण से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया है।

#### एआई का किया जा रहा इस्तेमाल

जयराम ने कहा कि आयोग विवादित ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी लगातार छिपा रहा है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर को केंद्रीकृत तरीके से अंजाम देने के लिए किया गया है।उन्होंने कहा, भारतीयों को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेजके खुलासे से यह क्यों पता चला कि ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर उसी ने विकसित किया है?आयोग ने इस जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया? आयोग एसआईआर और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में एआई के इस्तेमाल से बार-बार इनकार क्यों कर रहा है?

---

# डॉक्टर दंपती को 11 लाख रुपए के लिए धमकी

मेरठ, पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर दंपती ने तीन लोगों पर बकाया रकम नहीं लौटाने, झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई। शिकायत के आधार पर पल्लवपुरम पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंसल कोर्टयार्ड कॉलोनी निवासी विजय कुमार शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उनकी पत्नी डॉ. ऋचा शर्मा चिकित्सक हैं।

---

**न्यायालय नजूल अधिकारी**
**अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०**
**रा०प्र०क्र०- 64102/अ-6/2026-27**
**ईश्तहार**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण मंजूलता सोनी बेवा स्व. लखन प्रसाद, जयदेव सोनी आ.स्व. लखन प्रसाद, दोनों निवासी दरीपारा अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया है, कि आवेदकगण के पति/पिता स्व० लखन प्रसाद के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला-दरीपारा स्थित नजूल भूखण्ड क्र. 3766, 3767, 3768 रकबा क्रमशः 0.03, 0.03, 0.01 एकड़ भूमि है। भूधारक लखन प्रसाद की मृत्यु दिनांक 18.06.2004 को हो गई है। तद्धपरांत उक्त आवेदित भूमि से स्व० लखन प्रसाद का नाम विलोपित करते हुये आवेदकगण द्वारा स्वयं के नाम से फौति नामांतरण किये जाने हेतु स्व० लखन प्रसाद के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 05/11/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक- 23/10/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

**न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर**
**जिला-सरगुजा (छ०ग०)**
**रा०प्र०क्र०-/अ-6-अ/2025-26**
**ईश्तहार**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पूर्णिमा टोप्पो पति गंगाराम टोप्पो पिता पंचमराम, निवासी भट्ठीरोड, केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदिका के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 1278/3 रकबा 0.032 हे. स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदिका के पिता का नाम त्रुटिवश सिराजुद्दीन सिद्दीकी अंकित हो गया है जबकि आवेदिका के पिता का वास्तविक नाम पंचम राम है। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपने पिता का नाम सिराजुद्दीन सिद्दीकी के स्थान पर पंचम राम दर्ज कर त्रुटि सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 20/11/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 28/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

तहसीलदार
अम्बिकापुर

**न्यायालय नजूल अधिकारी,**
**अम्बिकापुर जिला-सरगुजा**
**रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26**
**ईश्तहार**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका हेमन्त श्यामजी परमार आ०/पति श्यामजी हरि परमार जाति, निवासी डी०सी० रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-राम मंदिर मैदान, शीट नम्बर-11 क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4813/78 रकबा 0.03 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत्तः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-11.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः-26.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

**न्यायालय नजूल अधिकारी,**
**अम्बिकापुर जिला-सरगुजा**
**रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26**
**ईश्तहार**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती इंदु देवी आ०/पति लक्ष्मीनारायण अग्रवाल जाति अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया निवासी अग्रसेन वार्ड है कि मोहल्ला-खरसिया रोड़, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2823/20, 2824/13 रकबा 0.02 1/4, 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.10.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 15.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

---

# हाईकोर्ट ने मेरठ एसएसपी को 45 मिनट खड़ा रखा

### शादी से मुकरने वाले को पेश नहीं किया था, एसएसपी बोले- मेरे अफसरों से चूक हुई

बीबीजीटीएस मूर्ति, एसएसपी मेरठ

मेरठ ,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को मेरठ एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को 45 मिनट तक कोर्ट में खड़ा रखा। मामला शादी का वादा करके जमानत लेने और बाद में मुकरने से जुड़ा है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर रस्ढ को उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। लेकिन, एसएसपी के जूनियर पुलिस अफसरों ने आरोपी को हाईकोर्ट में नहीं पेश करके सीजेएम की अदालत में पेश कर दिया था। सीजेएम ने आरोपी को जेल भी भेज दिया था। रस्ढ ने हाईकोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि मैं छुट् ?टी पर था। मेरे जूनियरों से चूक हुई है। इसके बाद जज अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आचरण पर भी गंभीर नाराजगी जताई। कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए आदेश की प्रति मेरठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। जिससे उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई पर विचार किया जा सके। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में पिछले साल एक लड़की के साथ नितीश उर्फ सिद्धांत उर्फ सेठी ने शादी का झांसा देकर रेप किया था। हाईकोर्ट में उसने लड़की से शादी करने का वादा कर जमानत मांगी। 18 मार्च, 2026 को सेठी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत मिलते ही सेठी ने अपना वादा तोड़ दिया। इस पर लड़की ने हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने आरोपी सेठी की जमानत रद्द करके उसे कोर्ट में हाजिर करने के लिए 28 सितंबर, 2026 को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कई तारीखों के बाद भी पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश नही किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को मेरठ रस्ढ को व्यक्तिगत पेश होने के आदेश दिए थे। शनिवार को सुनवाई के दौरान लड़की और आरोपी सेठी दोनों कोर्ट में मौजूद थे। जब कोर्ट ने सेठी से पूछा, तो उसने लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ?इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जमानत लेते समय दी गई अंडरटेकिंग का सीधा उल्लंघन किया है। कोर्ट ने तत्काल उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद आरोपी सेठी को जेल भेज दिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट से 28 सितंबर को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हाईकोर्ट लाने की जगह सीजेएम, मेरठ की अदालत में पेश कर दिया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस लापरवाही का पता चलते ही हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया इसके बाद शनिवार को हाईकोर्ट में खुद एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति पेश हुए। उन्होंने बताया कि वह 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अवकाश पर थे।

# गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 9 नवंबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक जेन्स-2101/3340/2026-जीएडी-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था।

# चक्रवात 'अर्नब' को लेकर छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ने की संभावना के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चक्रवात के मद्देनजर 27 से 29 अक्टूबर तक आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े।

## शून्य जनहानि का लक्ष्य और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और मौसम संबंधी चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। बैठक में मुख्य जोर शून्य जनहानि सुनिश्चित करने पर रहा। विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर

जिलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जहां तेज हवाएं चलने की संभावना है। राहत शिविरों को 24 घंटे संचालित रखने और उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव को चिकित्सा सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के प्रबंध करने को कहा गया है। किसानों को फसलों से संबंधित विस्तृत एडवाइजरी जारी करने तथा चक्रवात से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

## बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुचारू रखने के निर्देश

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि तेज हवाओं से कच्चे मकानों को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बिजली के खंभे गिरने से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए विद्युत विभाग को तैयार रहने को कहा गया है।

# लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम, अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलें - राज्यपाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**आईटीएम विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर**

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने युवाओं से अपने नए विचारों को स्टार्टअप में बदलने, नवाचार को अपनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है और युवाओं के विचार देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। राज्यपाल आज आईटीएम विश्वविद्यालय, रायपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, चार शोधार्थियों को पीएचडी तथा 464 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गईं।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। युवा अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देकर नए उद्यम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी क्षमता, ज्ञान और रचनात्मकता के बल पर रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन की एक पारी के समापन और दूसरी पारी की शुरूआत का प्रतीक है। डिग्री केवल एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल के माध्यम से परिवार, समाज और देश के प्रति दायित्व निभाने का अवसर है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही-गलत का विवेक विकसित करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

राज्यपाल ने कहा कि आज के विद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मोबाइल के युग में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने डिजिटल लत और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। जरूरत के अनुसार ही मोबाइल का उपयोग करने तथा परिवार, मित्रों और समाज के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने शांति और सुरक्षा से विकास को गति मिलने की बात कही और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के बाद बने विकास के अवसरों तथा बस्तर में आजीविका के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामचंद्र जहांगीर ने स्वागत भाषण दिया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष वी.के. गोयल ने भी संबोधित किया।

# रायपुर से नागपुर जा रहे पिकअप के गुप्त चेंबर मे 4 करोड़ रुपये मिले

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

दुर्ग। जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो मैक्स पिकअप से 4 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। खुसीपार थाना क्षेत्र के डबरापारा के पास हुई कार्रवाई में वाहन के पिछले हिस्से में बनाए गए विशेष गुप्त चेंबर से नकदी मिली।

## रात 11 बजे रोका गया पिकअप

पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन में बड़ी मात्रा में नकदी रायपुर से नागपुर ले जाई जा रही है। इसके आधार पर पुलिस टीम ने डबरापारा के पास रात करीब 11 बजे सफेद रंग के बोलेरो मैक्स पिकअप (क्रमांक सीजी 04 क्यू 5996) को रोककर जांच की।

## पिछले हिस्से में मिला गुप्त चेंबर

जांच के दौरान पुलिस को वाहन का पिछला हिस्सा मॉडिफाई कर पूरी तरह बंद किया हुआ मिला। संदेह के आधार पर सघन तलाशी लेने पर वहां एक विशेष गुप्त चेंबर मिला। इसे खोलने पर अंदर छिपाकर रखी गई भारतीय मुद्रा बरामद हुई।

## दो लोगों से पूछताछ जारी

पुलिस के अनुसार, वाहन में भवेशभाई जीनाभाई डाभी चालक के रूप में और विष्णुदेव दुबे सवार थे। दोनों से बरामद रकम के वास्तविक स्वामित्व, उसके स्रोत और इसे नागपुर ले जाने के उद्देश्य के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नकदी के वित्तीय स्रोत और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच के लिए आयकर विभाग को भी सूचना भेजी जा रही है।

# प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार: वित्त मंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

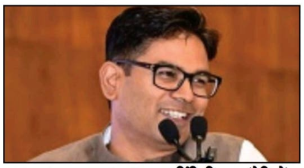

दुर्ग। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी ने देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया है। वित्त मंत्री चौधरी दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित पृथ्वी पैलेस में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ टैक्स टेक समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव तथा जीएसटी अपीलीय अधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के उपकर प्रचलित थे। अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के कारण व्यापारियों को अनेक प्रक्रियागत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन करों को एकीकृत कर देश को एक साझा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से व्यापारियों पर कर अनुपालन का बोझ कम हुआ है और कारोबार सुगम हुआ है। भारतीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगी टैक्स प्रैक्टिस की कार्यप्रणाली

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय तकनीकी परिवर्तन और नवाचार का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। कर प्रशासन, लेखांकन, विधिक अनुसंधान, दस्तावेजों के विश्लेषण और कर अनुपालन जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित तकनीकों का उपयोग नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य करदाताओं और शासन के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें बदलती तकनीकों और आधुनिक डिजिटल उपकरणों की जानकारी होना आवश्यक है।

## कानून की शिक्षा में जीएसटी को शामिल करने का सुझाव

कार्यक्रम के दौरान टैक्स बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने विधि शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीएसटी कानून को शामिल करने का सुझाव रखा। प्रतिनिधियों ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान ही जीएसटी कानून की व्यावहारिक जानकारी मिलने से उन्हें भविष्य में बेहतर व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

# शॉर्टकट के चक्कर में खतरे से खेल रहे छात्र, हाफ नदी के जर्जर एनीकट से रोजाना आवाजाही

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कवर्धा। जिले से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जिले के अंतिम छोर पर स्थित पंडरिया विकासखंड के ग्राम दामापुर में विद्यार्थी रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। यहां हाफ नदी के शिवगंगा क्षेत्र में बना एनीकट जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बावजूद स्कूली बच्चे कम दूरी तय करने के लिए इसी टूटे हुए एनीकट को पार कर स्कूल आते-जाते हैं।

## शॉर्टकट के चक्कर में खतरे से खेल रहे विद्यार्थी

जानकारी के अनुसार, ग्राम दामापुर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी प्रतिदिन हाफ नदी के क्षतिग्रस्त एनीकट को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों के लिए स्कूल आने-जाने का दूसरा सुरक्षित

रास्ता भी उपलब्ध है। नदी पर पुल भी बना हुआ है, लेकिन उस रास्ते से स्कूल पहुंचने के लिए लगभग एक से दो किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इसी दूरी से बचने के लिए विद्यार्थी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, यह रास्ता बेहद जोखिम भरा है। एनीकट का एक हिस्सा टूट चुका है और वहां पानी जमा है।

## टूटे एनीकट के नीचे गहरा पानी, हादसे की आशंका

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, एनीकट में फिलहाल पानी का बहाव अधिक नहीं है, लेकिन क्षतिग्रस्त हिस्से में पानी भरा हुआ है। नदी का यह हिस्सा काफी गहरा बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बच्चा संतुलन खोकर पानी में गिर जाए और उसे तैरना नहीं आता हो, तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। विशेष रूप से बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने और पानी का बहाव तेज होने पर यह रास्ता और अधिक खतरनाक हो सकता है।

## कीचड़ और पानी से खराब हो रही स्कूल ड्रेस

क्षतिग्रस्त एनीकट से होकर गुजरने वाले विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पार करते समय बच्चों के कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। कई बार पानी से उनकी स्कूल ड्रेस भी भीग जाती है। पानी में भीगने और जूते खराब होने के डर से कुछ बच्चे जूता-मोजा पहनकर भी नहीं आ पा रहे हैं।

## हर साल अस्थायी मरम्मत, स्थायी समाधान का इंतजार

ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्षतिग्रस्त एनीकट की स्थायी मरम्मत नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि हर साल एनीकट के दोनों छोर पर मिट्टी डालकर अस्थायी मरम्मत कर दी जाती है। लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित नहीं कर पाती। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्कूल पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग और पुल उपलब्ध हैं।

# शहीद गुंडाधुर की धरती से लिखी जा रही बस्तर में बदलाव की कहानी

## सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा में तब्दील कर दूरदराज के गांवों में पहुंचाई जा रही शासन की विभिन्न योजनाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर रहने वाले बस्तर के गांवों में अब विकास और विश्वास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। कभी जिन क्षेत्रों में खौफ का साया रहता था, अब वहां सुरक्षा कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 70 कैंपों को इन सेवा डेरों में बदला जा रहा है।

## विकास की मुख्यधारा से जुड़ता बस्तर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर आज नक्सलवाद के प्रभावों से मुक्त हो रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से आज सुदूर अंचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

## शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा: सुशासन और जनविश्वास का प्रतीक

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर जिले के नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में देश

के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। नेतानार वही ऐतिहासिक भूमि है जो बस्तर के महान जननायक शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वर्ष 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी।

## एक ही छत के नीचे मिल रही हैं तमाम सरकारी सुविधाएं

पहले बस्तर के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने या जाति-निवास प्रमाण पत्र के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। अब सेवा डेरा के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध हो गई हैं। डिजिटल सेवाएं, आधार अपडेट, केवाईसी, मोबाइल लिंक और प्रमाण पत्र जैसी ऑनलाइन सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे गांव में ही पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने जैसी बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं।

## महिला स्व-सहायता समूहों से आ रही आर्थिक क्रांति

नेतानार में गुंडाधुर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग बताती हैं कि इस कार्य से जुड़कर महिलाएं सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने की राह पर हैं। स्थानीय परंपरा को सहेजते हुए पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करने और उसकी बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जबकि धान की भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में हो रहा है। इसके अलावा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

## आधुनिक बाजार और बेहतर पैकेजिंग से जुड़ रहा बस्तर

इन उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अब पेशेवर संस्थानों की मदद ली जा रही है।

# चक्रवाती तूफान से संभावित भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड रहे आपदा प्रबंधन टीम : रेना जमील

## 0 शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं पर विशेष निगरानी के निर्देश 0 कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

**प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन**

**सूरजपुर।**सोमवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में यहां संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने राज्योत्सव की तैयारियों, संभावित भारी बारिश, धान खरीदी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागीय कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की।

कलेक्टर ने चक्रवाती तूफान के प्रभाव से संभावित स्थिति में भारी बारिश को देखते हुए संबंधित अधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जलाशयों और बांधों के जलस्तर की नियमित निगरानी रखते हुए संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला एवं अनुभाग स्तर पर कंट्रोल रूम, राहत केंद्रों की व्यवस्था व्यवस्था के साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधाएं, आवश्यक दवाइयां एवं राहत-बचाव की तैयारियां रखने को कहा है। ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। राज्योत्सव के तैयारियों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला, तहसील एवं जनपद स्तर के सभी शासकीय भवनों में रोशनी करने को कहा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण हो और आवेदकों से सकारात्मक फीडबैक भी प्राप्त करें। इस दौरान जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर तथा जनशिकायत के लंबित प्रकरणों को आगामी समय-सीमा की बैठक से पहले निराकरण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा के दृष्टिगत आगामी तीन माह तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक अवकाश नहीं लेने को कहा। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अनावश्यक शिक्षकों की अनुपस्थिति पर नोटिस जारी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व में अनुपस्थित शिक्षकों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य शिविरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग की जानकारी ली। टीकाकरण की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध साप्ताहिक उपलब्धि प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग बढ़ाने को कहा। उन्होंने आगामी माह में संभावित प्रसव वाली महिलाओं, विशेषकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की नियमित निगरानी करने और सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी बीपीएम को अपने कार्यों में गंभीरता लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा कर किसान पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता एवं सत्यापन की भी जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर श्रीमती नयन तारा सिंह तोमर, राम सिंह ठाकुर, प्रशांत कुशवाहा, एसडीएम सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

### सतर्कता जागरूकता सप्ताह, अधिकारियों ने ली सत्यनिष्ठा की शपथ

जिले में सोमवार से आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह की संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर रेना जमील की उपस्थिति मे जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।

1 नवंबर तक चलने वाले जागरूकता सप्ताह की थीम सत्यनिष्ठा से समृद्धि रखी गई है। शपथ में सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा से कार्य करने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय रूप से आवाज उठाने और देश के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

### जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं

आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं शासकीय सेवाओं का लाभ सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी। एवं प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

## कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमला सक्रिय, गांवों में गिरदावरी व डिजिटल क्रॉप सर्वे का सत्यापन

**बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन।** कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में फसल गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शंकरगढ़ तहसील के ग्राम नावाडीह एवं डीपाडीहखुर्द तथा ग्राम कृष्णनगर (धमनी) में राजस्व अमले ने खेतों में पहुंचकर गिरदावरी की, वहीं विकासखंड वाड्रफनगर की रघुनाथनगर तहसील के ग्राम बलंगी और गैना में डिजिटल क्रॉप सर्वे का भौतिक सत्यापन किया गया।

सत्यापन के दौरान खेतों में बोई गई फसलों का मिलान अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों से किया गया। सटीक फसल रिकॉर्ड से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय सहित शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। जिला प्रशासन द्वारा यह कार्य समय-सीमा में त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण कराने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।

## सुरक्षित बचपन अभियान, छात्रों को दी गई पॉक्सो एक्ट एवं साइबर सुरक्षा की जानकारी

### शा.बा.उ.मा.वि. में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम

**प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन**

**सूरजपुर।** बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण, उनके अधिकारों एवं सुरक्षित वातावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को यहां के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित इस अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराना तथा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान की थीम जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार तथा मूल संदेश हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी है।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमांशु पण्डा उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की सरल एवं सहज भाषा में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा एवं अधिकारों का संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग, ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरतने तथा किसी भी अनुचित परिस्थिति में विश्वसनीय व्यक्ति एवं संबंधित प्राधिकरण से सहायता लेने के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, विधिक सहायता एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में बताया गया। अभियान के तहत प्रथम चरण में 26 से 31 अक्टूबर तक एक सप्ताह का गहन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जबकि द्वितीय चरण में 12 नवंबर से विद्यालय स्तर पर क्षमता निर्माण एवं जागरूकता गतिविधियां निरंतर संचालित की जाएंगी।

यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष थॉमस एक्का के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण की सचिव सुश्री पायल टोपनो के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुजूर, प्रभारी शिक्षक ओमप्रकाश राजवाड़े तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स सत्य नारायण एवं उमेश राजवाड़े उपस्थित रहे।

# कल प्रेमनगर आएंगे मुख्यमंत्री, कलेक्टर एवं एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा

## कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश

**प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन**

**सूरजपुर।** जिले के प्रेमनगर में बुधवार 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने सोमवार को नगर पंचायत प्रेमनगर पुष्प वाटिका के समीप कार्यक्रम स्थल पहुँचकर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, आवागमन, हेलीपैड स्थल, सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जायेगा। जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागीय स्टॉल लगाई जाएगी। पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया जाएगा। तीरंदाजी प्रतियोगिता, युवा संवाद आयोजन सहित दिव्यांजनों हेतु शिविर भी लगाई जाएगी। कलेक्टर श्रीमती जमील ने उपस्थित सभी अधिकारियों को सभी तैयारियाँ निर्धारित तिथि से पूर्व समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले,अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, प्रशांत कुशवाहा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

# प्रधानमंत्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध, भाजयुमो ने फूंका खरगे का पुतला, किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प

**प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन**

**सूरजपुर।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा की गई अभद्र एवं अमर्यादित बयानबाजी के विरोध में सोमवार को भाजयुमो ने उग्र प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित अग्रसेन चौक पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी के मार्गदर्शन एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खरगे का पुतला दहन किया गया। ?इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और वहां तैनात पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प और झूमाझटकी हुई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के कड़े प्रयास किए गए, लेकिन आक्रोशित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हुए इस कड़े संघर्ष के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञात हो कि यह विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के निर्देशन एवं भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के आह्वान पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर

सुनिश्चित किया गया था।

?कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि देश के सर्वमान्य और लोकप्रिय जननेता के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की ओछी मानसिकता और हताशा को दर्शाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और देश का युवा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रितेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष संत सिंह, जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी, दीपक गुप्ता, बबलू गुप्ता, नगरपालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, वार्ड पार्षद बिसेन तायल, सोनू गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, मंडल महामंत्री नीरज जिन्दिया, भाजयुमो जिला मंत्री सहीम अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी दीक्षित वर्मा, कार्यालय मंत्री सोनू साहू, विशाल गुप्ता, विक्की सोनवानी, मंडल अध्यक्ष दिलीप साहू, महामंत्री हर्ष गुप्ता, महेंद्र साहू, गौरी शंकर साहू, अमन साहू, प्रिंस साहू, शानू साहू, गौरव दुबे, उमेंद्र राजवाड़े, हेमंत बैगा, पटेल ठाकुर, राजू साहू , कृष्णा राजवाड़े, भुनेश्वर साहू , बब्लू साहू, मनोज साहू, महेंद्र साहू, रविंद्र साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे।

# जिले में जल जीवन मिशन योजना पर लगा ग्रहण, भुगतान के अभाव में नहीं हो रहे काम

## आज रायपुर में अर्धनग्न हो कर भीख मांगेंगे जल जीवन के ठेकेदार

**प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन**

**सूरजपुर।** जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में हर घर जल योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुए थे लेकिन विभाग के द्वारा पहले पानी की व्यवस्था करनी थी उसके बाद हर घर नल कनेक्शन हेतु निविदा आमंत्रित करनी थी परंतु विभाग द्वारा पहले हर घर नल योजना के कार्य पूर्ण करा लिए अब पानी की व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी की गई है। पी एच ई ठेकेदार संघ के द्वारा विभाग को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जिला की समस्त समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है पर वह पूर्ण नहीं हुआ है।

11 एमवीएस योजना में से 6 योजना की निविदा निष्पादित नहीं हुई है. यह भी विचारणीय है कि 11 एमवीएस योजना अंतर्गत 543 में से 413 ग्राम को एसवीएस योजनाए जल आपूर्ति हेतु आश्रित है। आश्रित योजनाओं का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जबकि इन्हें न तो जलापूर्ति मिल पा रही है न ही इनका रनिंग बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है। जल जीवन मिशन संचालक द्वारा 19 फरवरी 2026 को आदेश क्रं. 547 में रनिंग बिल भुगतान अनुबंधित राशि का मात्र 70 प्रतिशत राशि तक भुगतान हेतु आदेश किया गया जिसके बाद 11 अगस्त को आदेश क्रं. 2397 में 60 प्रतिशत राशि तक कर दिया गया। किन्तु विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जो प्रशासन की नीयत पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ शासन की महत्त्वाकांक्षी योजना की खिल्ली उड़ा रही है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा मौखिक आदेशों के तहत ठेकेदार को जल स्त्रोत उपलब्ध कराने विवश किया जा रहा है जबकि यह दायित्व स्पष्ट रूप से विभाग का है एवं इस हेतु एमवीएस योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की गयी थी। आधी से अधिक एमवीएस योजनाओं का अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ है एवं कार्यरत योजनाओं का भुगतान पिछले 1 वर्ष से नहीं होने के कारण इकाइयाँ कार्य बंद कर चुकी हैं। परिणाम स्वरूप आश्रित एसवीएस योजनाएं भुगतान की बाट जोह रहीं है। अब यदि जलस्त्रोत भी उपलब्ध है तो ठेकेदारों के पास कार्यशील पूंजी नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण करना असंभव है. केंद्र द्वारा वर्ष 2028 तक हर घर जल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु विभाग की नीतियों और जल जीवन मिशन के प्रति उदासीनता इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अवरोध बनी हुई है। प्रदेश स्तर पर अन्य जिलों की समस्याओं के साथ अपनी समस्या हेतु अर्धनग्न हो कर भीख मांगने के लिए आज 27 अक्टूबर को रायपुर में समस्त जल जीवन के ठेकेदार समूह ने एकत्रित होने का आह्वान किया है।

# जनहित के मुद्दों पर प्रेमनगर ब्लॉक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सड़क, स्वास्थ्य व बिजली की समस्या से निजात दिलाने की मांग

**प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन**

**सूरजपुर।** प्रेमनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को जनहित की प्रमुख समस्याओं को लेकर ब्लॉक स्तरीय धरना-प्रदर्शन एवं चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामानुजनगर से तारा मार्ग की जर्जर एवं अधूरी सड़क, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी तथा बढ़ती बिजली समस्याओं को लेकर आवाज उठाई गई।

कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक गुलाब कमरो, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशि सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के जागरूक लोग उपस्थित रहे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद यादव, मेंहदी यादव, स्माइल खान, रोहित कनौजे, दीपन मानिकपुरी तुलसी यादव, सुखमनिया जगते, , आलोक साहू, बसराम सोरी, असकरण गुप्ता, अखिलेश जायसवाल कमलेश्वर सिंह विजय देवांगन, रमेश साहू रोशन पावले धर्मेंद्र प्रजापति, विजय महंत, दिनेश बंजारा, नरेंद्र सिंह अरमो, बालेश्वर दास, भुवंती सरदार, आलोक जगते, विद्यावती सिंह, देवेंद्र कुमारी, हेमंती सिंह, झमन गणेश्वर, सत्यनारायण, पारस सारथी, रूपेश मरावी,, अरबाज अली, मोतीलाल, आदेश, रवि, श्रीराम पतिराम मनराज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है।

# अंतरराष्ट्रीय एथलीट अनिमेष कुजूर पहुंचे कमतरा, फुटबॉल फाइनल में दिया नशामुक्ति और सड़क सुरक्षा का संदेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**जशपुर।** कुनकुरी ब्लॉक के ग्राम कमतरा में आयोजित जूनियर फुटबॉल फाइनल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंतरराष्ट्रीय एथलीट अनिमेष कुजूर शामिल हुए। कार्यक्रम में डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, जनपद अध्यक्ष कुनकुरी श्रीमती सुशीला साय, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, डीएसपी यातायात के.आर. चौहान, अनिमेष के पिता डीएसपी अमृत कुजूर एवं माता डीएसपी रीना नीलम कुजूर सहित सरपंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

### युवाओं को दिया लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश

अनिमेष कुजूर ने युवाओं को समय का महत्व समझाते हुए कहा कि जिस भी क्षेत्र में काम करें, पूरी लगन और मेहनत से करें। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रायोजन के महत्व पर बात करते हुए बताया कि उन्हें प्यूमा और रिलायंस फाउंडेशन से प्रायोजन प्राप्त होता है, जिससे उन्हें फ्लाइट, होटल और खेल गतिविधियों में सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी मेहनत से बड़े संस्थानों का सहयोग पा सकते हैं।

### कमतरा के नशामुक्त होने पर जताई खुशी

अनिमेष ने ग्राम कमतरा के नशामुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सरपंच अभिषेक कुजूर सहित समस्त ग्रामवासियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और अन्य पंचायतों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेल में योगदान देते हैं, तो समाज तेजी से प्रगति करता है।

### साथी खिलाड़ी की मौत का जिक्र कर की मार्मिक अपील

सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए अनिमेष ने बताया कि तीन दिन पूर्व उनके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथी खिलाड़ी की बाइक से डिवाइडर से टकराने के कारण सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। उस समय उसने हेलमेट नहीं पहना था। यदि हेलमेट पहना होता तो जान बच सकती थी। उन्होंने युवाओं से हेलमेट पहनने, नशे में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

### डीआईजी एवं एसएसपी ने बढ़ाया उत्साहडी

आईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए विजेता-उपविजेता टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जशपुर के लिए गर्व की बात है कि अनिमेष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनिमेष के पिता अमृत कुजूर फुटबॉल और माता रीना नीलम कुजूर हॉकी की उत्कृष्ट खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से जशपुर में खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जिले में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी तैयार हो रही है, साथ ही फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन के मैदान उपलब्ध हैं। डीआईजी ने कहा कि सड़क हादसों में अधिकांश जनहानि यातायात नियमों की अनदेखी से होती है। दोपहिया पर हेलमेट और चारपहिया पर सीट बेल्ट जीवन के लिए जरूरी है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस और आमजन को मिलकर काम करना होगा।समापन पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया।

# युवा रत्न सम्मान योजना अंतर्गत आवेदन 30 तक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**जशपुरनगर।** संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर द्वारा संचालित युवा रत्न सम्मान योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना अंतर्गत दो श्रेणियों में सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रथम श्रेणी छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान (असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य) के तहत 01 युवा को 02 लाख 50 हजार रूपये एवं 01 संगठन को 05 लाख रूपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। द्वितीय श्रेणी युवा रत्न सम्मान के तहत सामाजिक, साहित्य, उद्योग, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन, कला एवं संगीत, लोककला सहित कुल 13 क्षेत्रों में 01-01 युवा को 01-01 लाख रूपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा।

खेल वर्ग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साहसिक खेल तथा पारंपरिक खेलों के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। योजना हेतु आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना तथा आयु 15 से 29 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। केन्द्र व राज्य शासन के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। आवेदन के साथ कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वैच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अथवा स्वयं द्वारा जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जशपुर को प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला स्तर पर आवेदन जमा करने की अवधि 01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है।

# मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बनगांव में तेजी से बन रहा एनीकट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**जशपुर।** मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में बनगांव एनीकट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। 5 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस एनीकट से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तथा किसानों को खेती-किसानी में लाभ मिलेगा।

### लोकेर एवं बनगांव के सैकड़ों किसानों को मिलेगा लाभ

इस एनीकट के निर्माण से लोकेर एवं बनगांव क्षेत्र की लगभग 170 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को फसलों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।एनीकट निर्माण से क्षेत्र में जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जल संचयन से स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी।

विभागीय जानकारी के अनुसार, बनगांव एनीकट का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद लोकेर एवं बनगांव के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बनगांव एनीकट का निर्माण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

# दीपावली से पहले जशपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, पत्थलगांव में 6 आदतन अपराधियों पर कार्रवाई, भेजे गए जेल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**जशपुर।** आगामी दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जशपुर पुलिस सतर्क हो गई है। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने, शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका वाले व्यक्तियों पर नजर रखने और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना पत्थलगांव पुलिस ने 6 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है।

### इन पर हुई कार्रवाई

थाना पत्थलगांव पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत कार्रवाई की। सभी को एसडीएम पत्थलगांव के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फकीर यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी तमता (बथान पारा), शिव कुमार पोर्ते, उम्र 44 वर्ष, निवासी खरकाता (बेल पारा), सिराज हुसैन, उम्र 26 वर्ष, निवासी मदनपुर इंजको, जगदीश वैष्णव, उम्र 34 वर्ष, निवासी तमता, संतोष नामदेव उर्फ बांगड़ा, उम्र 28 वर्ष, निवासी प्रेमनगर, सालिक तिर्की, उम्र 55 वर्ष, निवासी प्रेमनगर

(सभी थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर)। पुलिस के अनुसार इनके विरुद्ध गांव में बार-बार लड़ाई-झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायतें मिल रही थीं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है। दीपावली पर्व को देखते हुए संभावित विवादों पर नियंत्रण के लिए यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

### पुलिस की अपील

जशपुर पुलिस ने आम नागरिकों से दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, असामाजिक गतिविधियों अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को देने को कहा है।

# खड़गे के बयान पर सियासी संग्राम, कुनकुरी में पुतला दहन कर भाजयुमो ने जताया विरोध

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**कुनकुरी।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। बयान के विरोध में सोमवार को कुनकुरी बस स्टैंड पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर खड़गे का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस घटनाक्रम ने स्थानीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव को फिर चर्चा में ला दिया है। विवाद की शुरुआत रविवार को पटना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां एक कार्यकर्ता ने मंच से कहा कि जब तक विद्रोह नहीं होगा, मोदी सरकार नहीं हटेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित तौर पर कहा, "मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा।" इसी टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और इससे राजनीतिक संवाद की मर्यादा प्रभावित होती है। इसी मुद्दे को लेकर कुनकुरी में भाजयुमो कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने खड़गे के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के जरिए भाजयुमो ने कांग्रेस नेतृत्व के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

प्रदर्शन में भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष नितेश पारीक, एल्डरमैन चाणक्य चौहान, जिला कार्यसमिति सदस्य अभिषेक अग्रवाल और तरुण डनसेना, मंडल अध्यक्ष रंजित सोनी, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष जुनैद सहित कृष्णा साहू, राजा आलम, हसीब अंसारी, देवेंद्र सिंह, अमन वर्मा, संतोष यादव, रवि चौहान, लवीश गुप्ता, नीतीश शर्मा, मोहित बंग, अनुराग चौहान और मसरत हुसैन समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।

### बयान से बढ़ी राजनीतिक तल्खी

खड़गे की टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होने के संकेत हैं। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा से जोड़कर विरोध जता रही है, जबकि पूरे विवाद का केंद्र राजनीतिक मंच से इस्तेमाल की गई भाषा और उसके राजनीतिक मायने बने हुए हैं। कुनकुरी में हुआ पुतला दहन इसी राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद की स्थानीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। अब यह मुद्दा केवल एक बयान तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक मर्यादा, नेताओं की भाषा और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी की बहस का हिस्सा बन गया है।

# रिश्ते का खून! जमीन विवाद में फूफा ने भतीजे को कुल्हाड़ी से काटा, आरोपी गिरफ्तार

### 20 साल से ससुराल में रह रहा था आरोपी, गाली-गलौज के बीच उठाया खौफनाक कदम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**जशपुर।** जमीन के बंटवारे को लेकर चल रही पुरानी अदावत ने एक परिवार में खौफनाक अंत ले लिया। थाना तपकरा क्षेत्र के ग्राम जामबहार चिटकाटोली में फूफा ने अपने ही भतीजे की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया है।

### क्या है पूरा मामला?

मृतक की पत्नी सुमित्रा प्रधान ने थाना तपकरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 अक्टूबर 2026 की शाम उसका पति संतोष बाजार से घर लौटा था। वह अपने दादा से कह रहा था कि आज फूफा ससुर मनबोध के घर जाकर बात करेगा, और रात करीब 8 बजे घर से निकल गया। प्रार्थिया के अनुसार आरोपी मनबोध उसके घर के पास ही रहता है और जमीन बंटवारे को लेकर संतोष से अक्सर विवाद होता था। घटना की रात जब मनबोध के घर से लड़ाई की आवाज आई तो सुमित्रा वहां पहुंची। उसने देखा कि आंगन में उसका पति मृत पड़ा है, सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी के गंभीर वार के निशान थे और खून फैला था। आरोपी पास में ही कुल्हाड़ी रखकर बैठा था। रिपोर्ट पर थाना तपकरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

### पुलिस जांच में खुलासा

पुलिस ने बताया कि आरोपी लगभग 20 वर्षों से ससुराल जामबहार में घर जमाई के रूप में रह रहा है। मृतक संतोष उसकी पत्नी के भाई का बेटा था। घटना की रात संतोष घर में घुसकर जमीन को लेकर गाली-गलौज करने लगा, जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त की। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिलोक प्रधान, प्रधान आरक्षक अजय कुमार लकड़ा, रिझन भगत, आरक्षक महेन्द्र पैंकरा, पुनित साय, अरविन्द साय एवं नगर सैनिक रवि गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।

# ब्रेस्ट टैक्स पर फेसबुक पोस्ट को लेकर एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ऐसे मामलों में केस की क्या जरूरत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

**जशपुर।** जिले में 'ब्रेस्ट टैक्स' को लेकर फेसबुक पर पोस्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि पुलिस को बड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता रूपनारायण एक्का की अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

### कुनकुरी थाने में दर्ज है एफआईआर

कुनकुरी पुलिस ने रूपनारायण एक्का के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से धर्म का अपमान करने से और धारा 353(2) विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य या घृणा बढ़ाने के इरादे से झूठी जानकारी फैलाने से संबंधित है।

### हाईकोर्ट से नहीं मिली थी जमानत

एफआईआर के बाद एक्का ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो 15 दिसंबर 2025 को खारिज हो गई। दूसरी याचिका भी 3 जुलाई 2026 को खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जांच में सहयोग की शर्त पर कठोर कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि नोटिस के बाद भी एक्का थाने में पेश नहीं हुए हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उन्हें बुलाया जाए, वह पेश होंगे। अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

### फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा था?

यह मामला 13 अप्रैल 2025 को फेसबुक पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पोस्ट में हिंदू महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दीपक मिश्रा की शिकायत पर कुनकुरी थाने में केस दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि पोस्ट में 'ब्रेस्ट टैक्स' का जिक्र था। इसमें दावा किया गया था कि महिलाओं के स्तन ढकने पर लगाया जाने वाला टैक्स मुगल शासक औरंगजेब ने नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण ने लगाया था। यह इतिहास को लेकर एक राय थी, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन केवल ऐसी पोस्ट के आधार पर अपराध नहीं बनता। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इसी वजह से कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। जस्टिस महादेवन ने सवाल उठाया कि ऐसी पोस्ट के लिए एफआईआर की जरूरत क्या थी। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि लोगों के पास समय बर्बाद करने के लिए बहुत समय है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दर्रीपारा अंबिकापुर छ. ग. पिन नं. 497001 से मुद्रित व वार्ड क्र. 10 कुनकुरी जशपुर से प्रकाशित। संपादक - लक्ष्मण सिंह